Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 38
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शनिवार, 14 फरवरी, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 वाकायामा प्रीफेक्चर के साथ प्रौद्योगिकी, ...

4 तारिक की बीएनपी नहीं उस पार्टी का अब....

7 पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का ...

संक्षिप्त न्यूज

सरकार के प्रयासों से पराली जलाने के मामले लगातार घट रहे हैं : कृषि मंत्री चौहान

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में शुक्रवार को कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध कराने के कारण खास तौर पर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले लगातार घट रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में चौहान ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं है।

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यह सर्दियों में भी कुल प्रदूषण में केवल पांच प्रतिशत योगदान करता है। उन्होंने कहा कि उद्योग और वाहन भी मुख्य प्रदूषण स्रोत हैं, लेकिन अक्सर किसानों को दोषी ठहराया जाता है। उच्च सदन में कृषि मंत्री ने बताया कि हालांकि किसानों के लिए खेत साफ करने का आसान तरीका पराली जलाना है, लेकिन इसके कई नुकसान भी हैं।

"इनमें फसल के अनुकूल कीटों का नाश, मिट्टी की उर्वरता में कमी, पोषक तत्व और कार्बन की हानि शामिल है। इसी कारण सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन (क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट सीआरएम) योजना शुरू की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, जबकि इन मशीनों को किराए पर किसानों को उपलब्ध कराने वाले संस्थानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। चौहान ने कहा कि अब तक 3.5 लाख से अधिक किसानों को मशीनें दी जा चुकी हैं, जिनमें पंजाब के 1, 60, 296 किसान, हरियाणा के 1, 10, 550 किसान और उत्तर प्रदेश के 76, 135 किसान शामिल हैं। "इसके परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के मामले काफी हद तक घट गए हैं।"

विकसित भारत का संकल्पः

पीएम मोदी बोले- गुलामी के प्रतीक मिटाकर बना रहे स्वतंत्र भारत की पहचान

नई दिल्ली। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम सभी एक नए इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। 13 फरवरी का यह दिन भारत के विकास पथ में एक नई शुरुआत का गवाह है। आज हम सभी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें, जो ब्रिटिश सोच की हुकूमत को लागू करने के लिए बनी थीं, वहीं आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं।

मोदी ने कहा कि यहां से जो फैसले होंगे, वे किसी महाराजा की सोच को नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं।

उन्होंने कहा कि इस समय 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है। यह आवश्यक है कि विकसित भारत की कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, बल्कि हमारे कार्यस्थलों

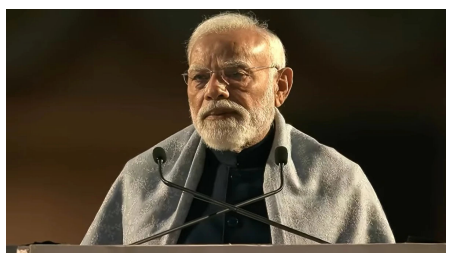

और इमारतों में भी दिखाई दे। जहां से देश का संचालन होता है, वह जगह प्रभावी भी होनी चाहिए और प्रेरणादायी भी होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसे पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थीं। करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थीं। इसके अलावा भी अनेक चुनौतियां थीं। मैं समझता हूं कि इन चुनौतियों के बारे में बताया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैसे, आजादी के इतने सालों बाद भी दिल्ली सरकार के अनेक मंत्रालय दिल्ली के 50 से भी ज्यादा स्थानों से चल रहे हैं। प्रतिवर्ष इन स्थानों के किराये में डेढ़ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8-10 हजार कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में यह बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने गुलामी की मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम पर नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाया। रेसकोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। यह केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, यह सत्ता के मिज़ाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था।

मोदी ने कहा कि हमारे इन फैसलों के पीछे एक गहरी भावना है, एक विजन है, जो हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और हमारे भविष्य को भारत के गौरव से जोड़ता है। जिस जगह को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहां न पर्याप्त सुविधाएं थीं और न ही आम नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था। हमने उसे कर्तव्य पथ के रूप में विकसित किया और आज वह स्थान परिवारों, बच्चों और देशभर से आने वाले नागरिकों के लिए जीवंत स्थल बन चुका है। नाम बदलने की पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है, इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है– स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान। गुलामी से मुक्त निशान।

सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियानः

शुभारंभ के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा- नैतिकता-आध्यात्मिकता बिना विकास अधूरा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक विशेष अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्थान के देशव्यापी अभियान 'सशक्त भारत के लिए कर्मयोग' की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने गुरुग्राम में स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती समारोह का भी शुभारंभ किया।

संबोधन में राष्ट्रपति ने क्या कहा?

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के संतुलित विकास के लिए केवल भौतिक प्रगति काफी नहीं है। इसके साथ नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि आर्थिक उन्नति से समृद्धि आती है और तकनीक से काम में कुशलता बढ़ती है। ये दोनों चीजें एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखती हैं। लेकिन अगर विकास में नैतिकता नहीं होगी, तो समाज का संतुलन बिगड़ सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा अनैतिक आर्थिक प्रगति धन और संसाधनों के केंद्रीकरण नुकसान और समाज के कमजोर वर्गों के शोषण का कारण बन सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि नैतिक मूल्यों के बिना तकनीक का इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है।

नैतिकता और आध्यात्मिकता को बताया समाज के लिए जरूरी

आध्यात्मिकता के महत्व पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमें ईमानदारी, दया और अहिंसा जैसे गुण सिखाती है। ये गुण एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आवश्यक हैं। जब हमारे विचार आध्यात्मिक होते हैं, तो हम स्वार्थ छोड़कर सबके भले के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व आध्यात्मिकता के आधार पर ही निष्पक्ष फैसले ले सकता है। ऐसे फैसले किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए होते हैं। इससे समाज में भरोसा बढ़ता है।

राष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के राजयोग और कर्मयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि कर्मयोग का अर्थ अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ऊंचे सिद्धांतों पर चलना है।

बिहार में बेटियों की चीखें सुनाई नहीं देती? रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार से पूछा सवाल

पटना **(एजेंसी)**। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बार नीतीश सरकार पर हमला बोला है। रोहिणी ने इस बार बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर तीखा प्रहार किया है। रोहिणी ने राज्य की वर्तमान स्थिति को लचर और लाचार बताते हुए सीएम से सवाल किया है कि क्या उन्हें बिहार की बेटियों की चीखें सुनाई नहीं देतीं?

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक अखबार की कतरन साझा की, जिसमें 12वीं कक्षा की एक 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का जिक्र है। छात्रा की मौत कोचिंग की चौथी मंजिल से गिरने के कारण हुई थी, जिसे परिजनों ने हत्या करार दिया है। इसी घटना का हवाला देते हुए रोहिणी ने आरोप लगाया कि बिहार में मां-बहन-बेटियों की अस्मत और जिंदगी खतरे में है।

रोहिणी ने केवल अपराध ही नहीं, बल्कि पुलिसिया कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच की आड़ में मामलों को दबाने की कोशिश करती है। दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी आत्ममुग्धता में डूबे हैं, उन्हें दुनिया भर में हो रही बिहार की बदनामी दिखाई नहीं दे रही।

गौरव गोगोई का सीएम सरमा पर सीधा हमला, बताया असम का 'सबसे असफल मुख्यमंत्री'

गुवाहटी। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें राज्य का 'सबसे असफल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री' बताया। बिस्वनाथ में एक विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए गोगोई ने आरोप लगाया कि असम में पुलिस जानबूझकर दर्ज एफआईआर की संख्या कम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती है, तो असम पुलिस उसकी शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं करती। कुछ दिन पहले, घोषणापत्र समिति के रूप में, हमने विभिन्न जिलों और आम जनता से पूछा था, और वकीलों के संगठनों ने हमें बताया था कि जहां पहले 3000-4000

एफआईआर दर्ज होती थीं, अब केवल 300-400 ही दर्ज हो रही हैं।

गोगोई ने आगे आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और नशीली दवाओं से संबंधित अपराध बढ़ गए हैं, लेकिन मामले औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री केवल एफआईआर की संख्या कम करके यह दिखाना चाहते हैं कि अपराध कम हो गया है। स्थानीय लोग, विशेषकर महिलाएं, न्याय से वंचित हो रही हैं। अपने हमले को और तेज़ करते हुए, कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री पर कानूनी कार्रवाई के ज़रिए आलोचकों को चुप कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गोगोई ने कहा कि क्या वह राजनेता नहीं हैं? क्या उन्हें जनता की अदालत पर भरोसा नहीं है? वह हमारी आवाज़ दबाने के लिए अदालत जाते हैं। आप दो-तीन लोगों को चुप करा सकते हैं, लेकिन असम की जनता सच्चाई जानती है।

उन्होंने आगे कहा कि वह कानूनी लड़ाई के बजाय राजनीतिक लड़ाई को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप (मुख्यमंत्री) में राजनेता के तौर पर हिम्मत है, तो हमसे सीधे मुकाबला कीजिए। मुझ पर पाकिस्तान से संबंध जोड़ने के आरोपों पर हम भी मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता।

रैली में भीड़ पर पाबंदी से भड़के एक्टर विजय, सीएम एमके स्टालिन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

चेन्नई। अपनी चुनावी सभा में मात्र 4,998 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद, तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) प्रमुख विजय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य द्वारा लागू किए गए मानक संचालन प्रक्रियाएं स्टालिन की कार्यप्रणाली हैं। सीलानाइकेनपत्ती में एक चुनावी रैली में सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने एमके स्टालिन सरकार पर आरोप लगाया कि वह तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) को राजनीतिक रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर रही है, जबकि अन्य को अनुमति दे रही है। विजय ने कहा कि वह सलेम केवल वोट मांगने नहीं, बल्कि न्याय मांगने आए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि जहां अन्य पार्टियों को अनुरोध करने पर तुरंत अनुमति मिल जाती है, वहीं तमिलगा वेट्री कज़गम को अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है। विजय ने कहा कि वे अन्य पार्टियों को सम्मेलन, सार्वजनिक सभाएं या हॉल में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति देते हैं और जगह उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सिर्फ हमें,

वे न तो जगह देते हैं और न ही देने की अनुमति देते हैं। अन्य पार्टियों के लिए, वे उपयुक्त स्थान और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि वे लोगों से मिल सकें या लोग उनसे मिल सकें। लेकिन मुझे, वे न तो यह सुविधा देते हैं और न ही देने की अनुमति देते हैं। यह कैसा न्याय है?

उन्होंने आगे कहा कि वे एसओपी की बात करते हैं। इसका पूरा नाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन मेरे लिए, इसका मतलब स्टालिन-ओह सॉरी, स्टालिन सर ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगता है। एहतियात के तौर पर, कार्यक्रम स्थल पर पार्टी सदस्यों और पदाधिकारियों के पहचान पत्रों का कड़ाई से सत्यापन किया गया। पुलिस दिशानिर्देशों के अनुसार, विजय के नेतृत्व वाली टीवीके रैली में केवल 4,998 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई। केवल क्यूआर कोड वाले प्रवेश पास धारकों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है, कोई अपवाद नहीं है।

जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती, प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों की जांच और यातायात को डायवर्ट किया गया। अधिकारियों ने कहा है कि इन उपायों का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना है, विशेष रूप से पिछले साल सितंबर में टीवीके की सभा के दौरान हुई भगदड़ की घटना के मद्देनजर, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले दिन में, स्टालिन ने घोषणा की कि कलाइग्नार महिला अधिकार योजना के तहत फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 3,000 अग्रिम रूप से जमा किए गए हैं, साथ ही ग्रीष्मकालीन विशेष पैकेज के रूप में अतिरिक्त 2,000 भी दिए गए हैं, जिससे इस महीने 1.31 करोड़ लाभार्थियों के लिए कुल राशि 5,000 हो गई है।

हंगामेदार रहा बजट सत्र का पहला चरण, 9 मार्च तक कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के संस्मरण से जुड़े विवाद को लेकर कई दिनों तक चले तीखे राजनीतिक वाद-विवाद के बाद शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। यह विवाद संसद के बाहर भी चर्चा का विषय बना रहा। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका दोनों सदन अब तीन सप्ताह के अवकाश पर चले गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 9 मार्च को फिर से शुरू होगी। बजट सत्र, जो 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संसद को दिए गए संयुक्त संबोधन के साथ शुरू हुआ था, 65 दिनों में 30 बैठकों के साथ समाप्त होगा। मध्यावधि अवकाश के दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान अनुरोधों की जांच करेंगी।

लोकसभा में दो फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव और इसका समर्थन करने के लिए भाजपा के दो सदस्यों के भाषण के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखनी

शुरू की तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण चर्चा नहीं हुई और न ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस पर जवाब हो सका। हालांकि लोकसभा में इस सप्ताह आम बजट पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इसका जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति नहीं देने और आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के मामले में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा महासचिव को एक नोटिस दिया है।

सूत्रों ने कहा कि नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण की शुरुआत होने पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। उच्च सदन में भी 2 फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच फरवरी को जवाब दिया था। राज्यसभा में नौ मार्च से आम बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हुई थी जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 फरवरी को दिया। कल ही उच्च सदन में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया गया था।

मेक इन इंडिया को मिला बूस्ट! एलसीए मार्क 1ए का उत्पादन स्टेबल, वायु सेना को मिलेंगे 180 नए जेट

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) मार्क 1ए कार्यक्रम की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल पांच इंजन उपलब्ध हैं; वहीं पांच विमान पहले से ही उड़ान भर रहे हैं। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय विक्रेताओं और मुख्य निर्माता, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के लिए उत्पादन काफी हद तक स्थिर हो गया है और इंजन की आपूर्ति स्थिर होने पर इसमें और सुधार होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि हथियार परीक्षण सफल रहे हैं, लेकिन भारतीय वायु सेना की कुछ आवश्यकताएं अभी तक पूरी तरह से पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ परिचालन संबंधी आवश्यकताओं में अभी भी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन 180 विमानों के नियोजित ऑर्डर के साथ, समय के साथ इस प्रणाली को परिष्कृत करके वायु सेना की सभी जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद है।

रक्षा सचिव ने कहा, एलसीए मार्क 1ए के लिए पांच इंजन उपलब्ध हैं और पांच विमान उड़ान भर रहे हैं... एक बार जब इस इंजन की आपूर्ति श्रृंखला स्थिर हो जाएगी, तो भारतीय विक्रेताओं, सिस्टम और इंटीग्रेटर (एचएएल) के संदर्भ में उत्पादन भी स्थिर हो जाएगा। वायु सेना द्वारा स्वीकृति के संबंध में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वायु सेना की कुछ आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है। हालांकि, हथियारों का परीक्षण सफल रहा है।

'भारत स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए तैयार रहे; स्थायी दोस्त या दुश्मन जैसी धारणा भ्रम' - सीडीएस जनरल अनिल चौहान

नई दिल्ली / पुणेः देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु जैसी अवधारणाएं भरोसेमंद नहीं होतीं। भारत को हर परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।

वे पुणे में दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित 'JAI' (जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन) सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश के साथ संबंध स्थायी नहीं होते। परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीतियां बदलती रहती हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा और विदेश नीति का आधार केवल और केवल राष्ट्रीय हित होना चाहिए।

रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर

सीडीएस ने कहा कि किसी भी गठबंधन या साझेदारी को रणनीतिक दृष्टिकोण से परखा जाना चाहिए। भारत को अपनी स्वतंत्र निर्णय क्षमता बनाए रखते हुए वैश्विक घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देनी होगी।

वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में तेज बदलाव

उन्होंने बताया कि वैश्विक सुरक्षा वातावरण तेजी से बदल रहा है और अनिश्चितता बढ़ रही है। आज व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, तकनीक तक पहुंच और महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग रणनीतिक दबाव के रूप में किया जा रहा है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे स्थापित सिद्धांतों को भी चुनौती दी जा रही है। लंबी दूरी और सटीक मारक क्षमता वाले हथियारों के विकास से बल प्रयोग की दहलीज कम हुई है।

पारंपरिक युद्ध की अवधारणा में परिवर्तन

जनरल चौहान ने कहा कि औपचारिक रूप से घोषित युद्ध अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा अब प्रॉक्सी युद्ध, सीमित सैन्य अभियानों, साइबर गतिविधियों और सूचना व संज्ञानात्मक युद्ध के रूप में सामने आ रही है। इन युद्धों में लक्ष्य केवल सेनाएं नहीं, बल्कि पूरा समाज होता है।

पश्चिम बंगाल में चुनावी फर्जीवाड़ा, जन्म से पहले बने जन्म प्रमाण ने खोली वोटर लिस्ट की पोल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बारानगर विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति पर राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की नज़र है, क्योंकि उसने हाल ही में संपन्न हुए मतदाता सूची संशोधन अभियान के दौरान कथित तौर पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। राज्य में इस अभियान के दौरान, संबंधित व्यक्ति ने एक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें

उसकी जन्मतिथि 6 मार्च, 1993 दर्ज थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि प्रमाण पत्र जन्म तिथि से दो दिन पहले, यानी 4 मार्च, 1993 को जारी किया गया था। जन्म से दो दिन पहले जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण असंभव मानते हुए, आयोग ने जल्द ही प्रमाण पत्र को अस्पष्ट घोषित कर दिया। इस मामले के चलते कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने मतदाता पंजीकरण अधिकारी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 का हवाला देते हुए चिन्हित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो झूठी जानकारी प्रस्तुत करने को दंडित करती है। इस बीच, पश्चिम बंगाल में राज्य चुनाव आयोग ने सत्यापन की अंतिम तिथि 21 फरवरी तय की है। आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। एसआईआर मामले की सुनवाई का लगभग पांच प्रतिशत हिस्सा अभी लंबित है।

वंदे भारत एक्सप्रेस में सांप रखने वाले आरोपी को मध्य रेलवे के आरपीएफ ने किया गिरफ्तार

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए 27 दिसंबर 2025 को वंदे भारत एक्सप्रेस में सांप रखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नासिक जिले का निवासी 37 वर्षीय आरोपी जगन अर्जुन भाले को 12 फरवरी 2026 को मुंब्रा से गिरफ्तार किया गया।

घटना 27 दिसंबर 2025 की है, जब ट्रेन संख्या 22225 के कोच ए-16 के शौचालय में एक सांप पाया गया। इसके तुरंत बाद शौचालय को बंद कर दिया गया और नियंत्रण कक्ष को सूचित किया गया। सोलापुर स्टेशन पर सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर शौचालय में सांप रखा था। इस संबंध में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145(बी), 147 एवं 153 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

सीसीटीवी फुटेज और एक गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ पथक ने कार्रवाई करते हुए मुंब्रा से आरोपी जगन अर्जुन भाले को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे कल्याण रेलवे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां उसे 14 दिनों की मजिस्ट्रेट कस्टडी (एमसीआर) में भेज दिया गया। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

मध्य रेलवे के आरपीएफ पथक ने कम समय में इस मामले को सुलझाकर एक बार फिर अपनी सतर्कता और जांच कौशल का परिचय दिया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसे मामलों का त्वरित निराकरण करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रयासों की मध्य रेलवे ने सराहना की है।

'हिंद-दी-चादर' के अवसर पर नवी मुंबई में व्यापक स्वच्छता अभियान

दिव्यांश

मुंबई। गुरु तेग बहादुर साहिब के शौर्य और बलिदान का स्मरण करते हुए 'हिंद-दी-चादर' के अंतर्गत विभिन्न उपक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में देश में अग्रणी नवी मुंबई महानगरपालिका द्वारा इसी क्रम में विशेष और व्यापक स्वच्छता अभियानों की शुरुआत की गई है।

इसी क्रम में आज तुर्भे विभाग अंतर्गत सेक्टर-9, सानपाड़ा गुरुद्वारा परिसर में सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया।

इसी प्रकार सेक्टर-7, घणसोली स्थित दिवंगत संजय बालाजी पाटील मैदान में प्लास्टिक मुक्त मैदान विषयक विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि दैनिक स्वच्छता कार्यों में मैदानों की सफाई शामिल नहीं थी, किंतु मैदानों की भी निश्चित अंतराल पर नियमित सफाई की जाए–ऐसे निर्देश आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे द्वारा दिए गए थे। उसी के अनुरूप 'हिंद-दी-चादर' के अंतर्गत मैदान स्वच्छता का यह उपक्रम प्रभावी रूप से प्रारंभ किया गया है।

इसके साथ ही घणसोली पाम बीच मार्ग एवं फुटपाथों पर जमी मिट्टी को हटाकर सड़क और पदपथ को पुनर्चक्रित पानी से धोया गया। इस प्रकार के स्वच्छता अभियान शासन द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'हिंद-दी-चादर' के अंतर्गत नवी मुंबई के सभी विभागों में संचालित किए जा रहे हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा 19 फरवरी, 2026 से 12 अतिरिक्त एसी लोकल तथा 3 नॉन-एसी ट्रेन सेवाओं की शुरुआत

पश्चिम रेलवे पर कुल लोकल सेवाओं की संख्या होगी

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर यात्री सेवाओं को और सुदृढ़ करते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा 19 फरवरी, 2026 से 12 अतिरिक्त एसी लोकल ट्रेन सेवाएं तथा 3 नई नॉन-एसी सेवाएं शुरू की जाएंगी। वातानुकूलित यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए तथा आम यात्रियों के लिए किफायती विकल्पों की निरंतर आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, पश्चिम रेलवे संतुलित एवं समावेशी आवागमन अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। सेवाओं में यह वृद्धि भीड़भाड़ कम करने तथा यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने में सहायक होगी। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 12 एसी लोकल सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिनमें से 11 सेवाएं मौजूदा नॉन-एसी सेवाओं के स्थान पर संचालित की जाएंगी, जबकि एक सेवा नई एसी सेवा होगी। इसके अतिरिक्त, तीन नई नॉन-एसी सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं। इस वृद्धि के साथ एसी सेवाओं की कुल संख्या 121 से बढ़कर

133 हो जाएगी तथा पश्चिम रेलवे नेटवर्क पर कुल लोकल सेवाओं की संख्या 1410 से बढ़कर 1414 हो जाएगी। शनिवार एवं रविवार को संचालित एसी सेवाओं की संख्या भी 77 से बढ़कर 106 हो जाएगी, जिससे विकेंड में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिक आराम और क्षमता उपलब्ध होगी। इसके अलावा, वर्तमान में भायंदर से बांद्रा के बीच संचालित एक स्लो लोकल सेवा को अब विरार से संचालित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा एवं बेहतर संपर्क उपलब्ध होगा। यह पहल मुंबई की जीवनरेखा कही जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाओं में अधिक सुरक्षित, कुशल एवं यात्री-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने की पश्चिम रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नई ट्रेन सेवाओं का विवरण परिशिष्ट-I में संलग्न है।

मुंबई में बड़ा एक्शन! लोढ़ा डेवलपर्स की शिकायत पर ही पूर्व निदेशक गिरफ्तार, 85 करोड़ के Fraud का मामला

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मुंबई स्थित रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा को 85 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी लोढ़ा डेवलपर्स की शिकायत के बाद हुई है, जो भारत की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। लोढ़ा डेवलपर्स ने पिछले साल एक बड़े घोटाले के सामने आने के बाद वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी वाले लेन-देन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लोढ़ा को इससे पहले मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के अनुसार, राजेंद्र लोढ़ा और कई अन्य लोगों पर जटिल लेन-देन की एक श्रृंखला के माध्यम से कंपनी से बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी करने का आरोप है। यह मामला सबसे पहले सितंबर 2025 में सामने आया, जब लोढ़ा डेवलपर्स ने राजेंद्र लोढ़ा और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने जांच शुरू की।

इसके बाद, राजेंद्र लोढ़ा और कई सह-आरोपियों को धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के संदेह में गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं ने तब से नकदी और सोने दोनों से जुड़े कथित गबन के कई मामले उजागर किए हैं। जांच के अनुसार, राजेंद्र लोढ़ा पर फर्जी भूमि अधिग्रहण, पहले से खरीदी गई जमीनों की पुनर्विक्रय और कंपनी की संपत्तियों के अवमूल्यन के माध्यम से कंपनी के धन को डायवर्ट करने की साजिश रचने का आरोप है। सबूतों से पता चलता है कि भूमि सौदों की आड़ में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप लोढ़ा डेवलपर्स को भारी नुकसान हुआ।

मुंबई और प्रयागराज के बीच यात्रियों की मांग पर 44 साप्ताहिक विशेष ट्रेन सेवा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे मुंबई के एलटीटी और प्रयागराज के बीच 44 साप्ताहिक विशेष ट्रेन सेवाएं चलाएगा। ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

एलटीटी-प्रयागराज-एलटीटी साप्ताहिक विशेष (44 सेवाएं)

ट्रेन संख्या 04102 साप्ताहिक विशेष, दिनांक 17.02.2026 से दिनांक 14.07.2026 तक प्रत्येक मंगलवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 16.55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 17.00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

ट्रेन का संचालन इस प्रकार होगा: (22 सेवाएं)

दिनांक 17.02.2026 से 24.02.2026 और दिनांक 07.04.2026 से 14.04.2026 तक विशेष ट्रेन के रूप में (4 सेवाएं)

दिनांक 03.03.2026 से दिनांक 31.03.2026 तक होली विशेष ट्रेन के रूप में (5 सेवाएं)

ग्रीष्मकालीन विशेष के रूप में दिनांक 21.04.2026 से 14.07.2026 तक (13 सेवाएं)

ट्रेन संख्या 04101 साप्ताहिक विशेष, दिनांक 16.02.2026 से दिनांक 13.07.2026 तक प्रत्येक सोमवार को शाम 18:00 बजे प्रयागराज से प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 14:55 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।

ट्रेन का संचालन इस प्रकार होगा: (22 सेवाएं)

दिनांक 16.02.2026 से दिनांक 23.02.2026 और दिनांक 06.04.2026 से दिनांक 13.04.2026 तक विशेष ट्रेन के रूप में (4 सेवाएं)

दिनांक 02.03.2026 से 30.03.2026 तक होली विशेष ट्रेन के रूप में (5 सेवाएं)

दिनांक 20.04.2026 से दिनांक 13.07.2026 तक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन के रूप में (13 सेवाएं)

ठहराव: कल्याण, इगतपुरी (केवल 04102 के लिए), नाशिक, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना और मानिकपुर। संरचना: 1 एसी-2 टियर, 4 एसी-3 टियर, 9 शयनयान श्रेणी, 8 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 सेकंड सीटिंग के साथ सामान सह गार्ड ब्रेक वैन ।

आरक्षण: विशेष ट्रेन संख्या 04102 के लिए बुकिंग दिनांक 14.02.2026 से सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट ".ैम्.म्द.ग्ह पर अग्रिम आरक्षण अवधि के अंतर्गत यात्राओं के लिए खुलेगी। ARP के बाद की यात्राओं के लिए बुकिंग संबंधित ARP तिथियों पर खुलेगी।

अनारक्षित कोच के लिए बुकिंग सामान्य शुल्क के साथ ळऊए प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। यात्री टिकट बुकिंग के लिए RailOne ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन विशेष ट्रेनों के ठहराव के विस्तृत समय के लिए, कृपया www.enquiry .indianrail.gov.in पर जाएं या NTES ऐप डाउनलोड करें।

मध्य रेल पर को मेगा ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल, मुंबई मंडल रविवार, दिनांक 15.02.2026 को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर मेगा ब्लॉक संचालित करेगा। विवरण इस प्रकार है:

मेन लाइन: माटुंगा-मुलुंड अप और डाउन फास्ट लाइन 11.05 बजे से 15.45 बजे तक

सीएसएमटी मुंबई से 10.36 बजे से 15.10 बजे तक चलने वाली डाउन फास्ट लाइन सेवाएं माटुंगा स्टेशन पर डाउन स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और माटुंगा और मुलुंड स्टेशनों के बीच अपने निर्धारित ठहरावों के अनुसार रुकेंगी और अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी। ठाणे से आगे जाने वाली फास्ट ट्रेनों को मुलुंड स्टेशन पर डाउन फास्ट लाइन पर पुनः डायवर्ट किया जाएगा।

ठाणे से सुबह 11:03 बजे से दोपहर 15:38 बजे तक चलने वाली अप फास्ट लाइन की सेवाएं मुलुंड स्टेशन पर अप स्लो लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी और मुलुंड और माटुंगा स्टेशनों के बीच अपने निर्धारित ठहरावों के अनुसार रुकेंगी। इसके बाद उन्हें माटुंगा स्टेशन पर अप फास्ट लाइन पर पुनः डायवर्ट किया जाएगा और वे अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 15 मिनट देरी से पहुंचेंगी।

हार्बर लाइन: कुर्ला और वाशी स्टेशनों के बीच हार्बर लाइन की अप और डाउन सेवाएं 11.10 बजे से 16.10 बजे तक।

सीएसएमटी मुंबई से वाशी/बेलापुर/पनवेल जाने वाली हार्बर लाइन की डाउन सेवाएं 10.34 बजे से 15.36 बजे तक और पनवेल/बेलापुर/वाशी से सीएसएमटी मुंबई की ओर जाने वाली हार्बर लाइन की अप सेवाएं 10.17 बजे से 15.47 बजे तक रद्द रहेंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान सीएसएमटी मुंबई - कुर्ला और पनवेल - वाशी खंडों पर विशेष उपनगरीय ट्रेन सेवाएं चलेंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान हार्बर लाइन के यात्री ठाणे-वाशी/नेरुल स्टेशनों के बीच 10.00 बजे से 18.00 बजे तक यात्रा कर सकते हैं।

बुनियादी ढांचे के रखरखाव और संरक्षा के लिए ये मेगा ब्लॉक आवश्यक हैं।

यात्रियों से असुविधा के लिए सहयोग करने की अपेक्षा है।

कांजुरमार्ग स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज गर्डर लॉन्चिंग हेतु विशेष यातायात एवं विद्युत ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेलवे द्वारा कांजुरमार्ग स्टेशन (कल्याण छोर) पर किलोमीटर 24/13-14 के बीच फुट ओवर ब्रिज के लिए 6 मीटर चौड़ाई के 4 गर्डरों को रोड क्रेन की सहायता से स्थापित करने हेतु विशेष यातायात एवं विद्युत ब्लॉक लिया जाएगा।

ब्लॉक की तिथि: 14/15 फरवरी 2026 (शनिवार/रविवार मध्यरात्रि) ब्लॉक की अवधि: 15 फरवरी 2026 को प्रातः 01:05 बजे से 04:35 बजे तक यातायात ब्लॉक खंड: विक्रोली से मुलुंड (दोनों स्टेशन को छोड़कर)

उपनगरीय ट्रेनों पर प्रभाव

1. ट्रेनों का निरस्तीकरण:

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-ठाणे लोकल (T-1), जो 15 फरवरी 2026 को 00:24 बजे सीएसएमटी से प्रस्थान करेगी – निरस्त रहेगी।

ठाणे-सीएसएमटी लोकल (T-2), जो 15 फरवरी 2026 को 04:04 बजे ठाणे से प्रस्थान करेगी – निरस्त रहेगी।

2. ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन:

सीएसएमटी-करजात लोकल (S-1), जो 15 फरवरी 2026 को 00:12 बजे सीएसएमटी से प्रस्थान करेगी, उसे माटुंगा और मुलुंड के बीच डाउन फास्ट लाइन पर परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। यह ट्रेन विद्याविहार, कांजुरमार्ग एवं नाहुर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।

यह ब्लॉक अधोसंरचना के रखरखाव एवं सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों से हुई असुविधा के लिए सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

पश्चिम रेलवे का रविवार को राम मंदिर एवं बोरीवली स्टेशनों के बीच जम्बो ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव कार्य हेतु रविवार, 15 फरवरी, 2026 को राम मंदिर एवं बोरीवली स्टेशनों के बीच अप फास्ट तथा 5वीं लाइन पर 10:00 बजे से 14:00 बजे तक चार घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक

अवधि के दौरान सभी अप फास्ट लाइन की ट्रेनें बोरीवली एवं अंधेरी स्टेशनों के बीच अप स्लो/छठी लाइन पर चलाई जाएंगी। इसी प्रकार, पाँचवी लाइन की सभी ट्रेनों को अंधेरी एवं बोरीवली स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा।

इस ब्लॉक के कारण कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी। साथ ही, कुछ अंधेरी एवं बोरीवली उपनगरीय सेवाएं हार्बर लाइन पर गोरेगांव तक चलाई जाएंगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

मध्य रेल

एलएचबी कोचों की मरम्मत

निविदा सूचना क्र. आरआर/पीआर/डब्ल्युसी/2139/2025-26/109

कार्य का विवरण: एलएचबी कोचों की जंग से संबंधित मरम्मत। **मात्रा:** रेट शेड्यूल के अनुसार, **निविदा समापन/ खोलने और समय की तिथि:** 10.03.2026, 16:00 बजे तक। निविदा विवरण और निविदा दस्तावेज **www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध है। निविदाएं वेबसाइट के माध्यम से केवल ई-टेंडरिंग प्रारुप में ही स्वीकार की जाएंगी।

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें 903

पश्चिम रेलवे

भंडार (स्टोर्स) विभाग

मार्च 2026 के दौरान पी-वे एवं अन्य विविध स्क्रैप की ई-नीलामी

विशेष सूचना: सभी स्टील क्रेताओं एवं री-रोलर्स के लिए

पी-वे स्क्रैप, रेल स्क्रैप तथा अन्य विविध स्क्रैप सामग्री के निपटान हेतु सार्वजनिक ई-नीलामी मार्च 2026 में नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।

प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	डिपो / मंडल	प्रभारी अधिकारी	संपर्क नं0
02/03/2026	10/03/2026	23/03/2026	रतलाम	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - रतलाम	07412230080 09752492750
05/03/2026	12/03/2026	20/03/2026	वडोदरा	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - वडोदरा	02652641592 09724091750
06/03/2026	17/03/2026	27/03/2026	साबरमती	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - साबरमती	02812476943 09724094770
09/03/2026	16/03/2026	24/03/2026	मुंबई सेंट्रल	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - मुंबई सेंट्रल	022-23094142 09004499006
09/03/2026	20/03/2026	30/03/2026	प्रतापनगर	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - प्रतापनगर	02652658858 09724093750
10/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	अहमदाबाद	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - अहमदाबाद	07922205888 09724093750
10/03/2026	17/03/2026	25/03/2026	राजकोट	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - राजकोट	02812476943 09724094770
11/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	दाहोद	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - दाहोद	02673241295 09724090455
11/03/2026	18/03/2026	27/03/2026	महालक्ष्मी	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - महालक्ष्मी	022-24929571 09004495750
17/03/2026	29/03/2026	27/03/2026	पारडी	उप मुख्य सामग्री प्रबंधक - महालक्ष्मी	022-24929571 09004495750
12/03/2026	19/03/2026	27/03/2026	भावनगर	वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक - भावनगर	02782444360 09724097750

सभी डिपो एवं मंडलों के लिए 31 मार्च को मेगा नीलामी। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित डिपो/मंडल अधिकारी से संपर्क करें। **टिप्पणी :** 1. रेलवे को ई-नीलामी से किसी भी लॉट को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है। 2. ई-नीलामी निर्धारित समय के अनुसार प्रारंभ होगी। 3. ई-नीलामी की कैटलॉग www.ireps.gov.in ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। 4. ई-नीलामी, डिजिटल हस्ताक्षर, पंजीकरण प्रक्रिया एवं सहभागिता से संबंधित किसी भी सहायता के लिए ऊपर उल्लिखित डिपो/मंडल अधिकारी से संपर्क करें। 5. सभी भुगतान लेन-देन ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से ही किए जाएंगे।

(क्रमांक: S/SIII/Auction Programme-1/मार्च 2026, दिनांक: 05.02.2026)

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: x.com/WesternRly 1107

वाकायामा प्रीफेक्चर के साथ प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत होगा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र और जापान के वाकायामा प्रीफेक्चर के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और आने वाले वर्षों में प्रौद्योगिकी, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने जापान के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की।

वाकायामा प्रीफेक्चर के गवर्नर मियाज़ाकी इज़ुमी के नेतृत्व में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल ने होटल ताज महल पैलेस में मुख्यमंत्री फडणवीस से भेंट की। इस अवसर पर महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुंबई में जापान के महावाणिज्यदूत यागी कोजी, वाकायामा विधानसभा के उपाध्यक्ष अकिज़ुकी फुमिनारी तथा जापान के सरकारी, विधायी, सांस्कृतिक, क्रीड़ा और औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई भारत की वित्तीय, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन की राजधानी है। महाराष्ट्र और वाकायामा को 'सिस्टर स्टेट्स' के रूप में मान्यता प्राप्त है और दोनों के बीच वर्षों से सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए हैं। वर्ष 2013 में दोनों क्षेत्रों के

बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे 2023 में नवीनीकृत किया गया। इस अवधि में संस्कृति, खेल, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय आदान-प्रदान हुआ है। अजंता क्षेत्र में जापानी पर्यटकों के लिए सुविधाओं के निर्माण सहित उन्हें आकर्षित करने के प्रयास भी किए गए हैं।

जापान की अपनी दो यात्राओं के दौरान वाकायामा और कोयासन की यात्राओं को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयासन विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण दोनों देशों की मित्रता का प्रतीक है। वर्ष 2023 में वाकायामा के दिवंगत गवर्नर की उपस्थिति में सूमो पहलवानों की एक टीम मुंबई आई थी। गेटवे ऑफ इंडिया पर सूमो और भारतीय कुश्ती के प्रदर्शन को नागरिकों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली। वर्तमान में जापानी सूमो पहलवान पुणे के बालेवाड़ी खेल परिसर में प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसे खेल आदान-प्रदान दोनों देशों में विश्वस्तरीय खिलाड़ियों के विकास में सहायक होंगे।

जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही। उनके कार्यकाल में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गईं। उन्होंने मुंबई में बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया, जिसमें 40 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो और देश का सबसे लंबा समुद्री पुल शामिल है।

अंतरिक्ष अनुसंधान में ग्रामीण छात्रों की भागीदारी बढ़ाने हेतु इसरो विज्ञान भ्रमण

आकाश से अंतरिक्ष तकः ग्रामीण विद्यार्थियों के सपनों को सरकार का समर्थन - अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे

'विजाभाज' आश्रम शालाओं के 100 विद्यार्थी विज्ञान प्रेरणा अभियान के अंतर्गत यात्रा में होंगे शामिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'विज्ञान प्रेरणा अभियान' के अंतर्गत 'विजाभाज' आश्रम शालाओं के 100 मेधावी विद्यार्थियों के लिए 15 से 20 फरवरी 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में एक विशेष शैक्षणिक विज्ञान भ्रमण का आयोजन किया गया है।

मंत्री सावे ने कहा कि ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, शोध-वृत्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपार अवसर उपलब्ध हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल कर रही है कि ग्रामीण विद्यार्थियों को भी ये अवसर प्राप्त हों।

उन्होंने बताया कि राज्य की विभिन्न 'विजाभाज' आश्रम शालाओं से मेरिट परीक्षा के माध्यम से 100 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को इसरो में उपग्रह

निर्माण, प्रक्षेपण तकनीक, जीवंत रॉकेट प्रक्षेपण तथा अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही, विज्ञान कार्यशालाओं तथा वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ संवाद के माध्यम से उन्हें अनुभवात्मक अधिगम का लाभ मिलेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक संस्थाओं से जोड़ना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना तथा उच्च शिक्षा के अवसरों के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

इस यात्रा के दौरान विद्यार्थियों की हवाई यात्रा की व्यवस्था की गई है और उनकी सुरक्षित एवं सुचारु यात्रा के लिए विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। विभाग ने यह भी बताया कि विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता का आवास, आवश्यक सुविधाएं और दैनिक उपयोग की सभी सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी। विभाग द्वारा इस प्रकार की पहल पहली बार लागू की जा रही है।

980 स्कूलों से 100 मेधावी विद्यार्थियों का चयन

राज्य की 980 'विजाभाज' आश्रम शालाओं के कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए एक मेरिट परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें से कुल 100 विद्यार्थियों–50 बालक और 50 बालिकाएं–का चयन किया गया है।

सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा पहली बार बैंड महोत्सव का आयोजन - सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशिष शेलार

मुंबई के बांद्रा स्थित बैंड स्टैंड में 14 से 16 फरवरी तक आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से इस वर्ष पहली बार बैंड महोत्सव का आयोजन 14 से 16 फरवरी के दौरान एम्फीथिएटर, बैंड स्टैंड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई में किया जा रहा है।

इस बैंड महोत्सव में महाराष्ट्र के विभिन्न बैंड दल भाग लेंगे। यह अनोखा बैंड महोत्सव पहली बार शासन की ओर से आयोजित किया जा रहा है।

मुंबई और पुणे पुलिस बैंड दल भी इसमें सहभागी हो रहे हैं।

14 फरवरी को मुंबई पुलिस बैंड, झंकार ब्रास बैंड, किले मच्छिंद्रगढ़ (सांगली), मास्टर रफी ब्रास बैंड (जलगांव) की प्रस्तुतियां होंगी।

रविवार, 15 फरवरी 2026 को पुणे पुलिस बैंड (पुणे), बाबूलाल ब्रास बैंड (नासिक), जनता बैंड पाटोदा (बीड), दर्यावर्दी ब्रास बैंड (मुळेखंड कोळीवाडा, रायगढ़) की प्रस्तुतियां आयोजित की जाएंगी।

समापन दिवस सोमवार, 16 फरवरी 2026 को पाइप बैंड पुणे (एसआरपी),

वेस्ट बैंड मुंबई तथा अमर बैंड (बारामती, पुणे) अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

बैंड महोत्सव की संकल्पना सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशिष शेलार की है और इस महोत्सव को सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सांस्कृतिक कार्य निदेशक श्रीराम पांडे ने सभी संगीत प्रेमी दर्शकों से इस महोत्सव का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

बैंड महोत्सव को मंच प्रदान करना और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा की विरासत को और अधिक समृद्ध करना– यही इस भव्य महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा भी इस अवसर पर बताया गया।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी के 350वें शहादत शताब्दी वर्ष के अवसर पर नागरिक बड़ी संख्या में सहभाग करें- जिला कलेक्टर जितेंद्र दुडी

पुणे।ः नवी मुंबई के खारघर में 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को आयोजित होने वाले 'हिंद-दी-चादर' कार्यक्रम में पुणे जिले के नागरिक बड़ी संख्या में सहभागी होकर सामाजिक एकता के संदेश को सशक्त करें–ऐसा आवाहन जिला कलेक्टर जितेंद्र दुडी ने किया है।

आज जिला कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की। इससे पूर्व महाराष्ट्र के नागपुर और नांदेड़ में श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी की 350वीं शहादत जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, और अब खारघर में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा।

जिला कलेक्टर दुडी ने कहा कि इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ सुनियोजित ढंग से कार्य करें, ताकि कार्यक्रम सुचारू, प्रभावी और समावेशी रूप से संपन्न हो सके। सामाजिक एकता, सेवा और राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, जिला परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिकाओं, शिक्षा विभाग, ग्राम पंचायतों, पुलिस व परिवहन विभाग तथा औद्योगिक क्षेत्र तक कार्यक्रम की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में सिख, सिकालकर, बंजारा, लबाना, सिंधी, मोहियाल, वाल्मीकि, उदासी तथा भगत नामदेव समुदाय की जनसंख्या अधिक है, वहां विशेष जनजागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कार्यक्रम के सांस्कृतिक पक्ष को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में भजन-कीर्तन, निबंध, वक्तृत्व, प्रतियोगी परीक्षाएं तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थियों में श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी के बलिदान से प्रेरणा लेने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 'स्वास्थ्य पखवाड़ा' मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही, प्रत्येक विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों की जियो-टैग की गई छायाचित्रों सहित विस्तृत रिपोर्ट को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी का बलिदान धार्मिक स्वतंत्रता, मानवता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। उनकी 350वीं शहादत जयंती के अवसर पर आयोजित यह 'हिंद-दी-चादर' कार्यक्रम समाज में भाईचारे, एकता और सेवा भाव को जागृत करने वाला एक ऐतिहासिक आयोजन सिद्ध होगा–ऐसा उल्लेख जिला कलेक्टर दुडी ने अपने आवाहन में किया।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य- आयुक्त नैना गुंडे

कार्यालय में आंतरिक समिति का गठन न करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

मुंबई(संवाददाता)।राज्य में दस से अधिक कर्मचारियों वाले सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों तथा निजी प्रतिष्ठानों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 'आंतरिक समिति' का गठन अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यह जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त नैना गुंडे ने दी। आंतरिक समिति का गठन न करने पर संबंधित मालिक या संस्था प्रमुख पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि यह उल्लंघन दोबारा किया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है अथवा दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के अनुरूप, महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम 2013) को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। गठित आंतरिक समिति की जानकारी केंद्र सरकार के शी-बॉक्स (shebox.wcd.gov.in) ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे शिकायतों के निवारण और निगरानी में आसानी होगी।

शशिकांत शिंदे का बड़ा दावाः

एनसीपी से मजबूर होकर अलग हुए थे अजित पवार, विलय के बाद संभालने वाले थे पार्टी की कमान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दिवंगत अजित पवार को अदृश्य ताकतों, धमकियों और झूठे आरोपों के जाल के कारण मूल एनसीपी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फरवरी 2026 के पार्टी मुखपत्र राष्ट्रवादी में प्रकाशित श्रद्धांजलि लेख में शिंदे ने कहा कि बीते चार-पांच महीनों से पिछली गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही थी और दोनों गुटों के विलय की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी।

बयान पर उठा विवाद

शिंदे ने दावा किया कि हाल के नगर निगम और जिला परिषद चुनाव अभियानों में अजित पवार की सक्रिय भूमिका उनके घर वापसी के संकेत के रूप में देखी जा रही थी। हालांकि, शिंदे के अदृश्य ताकतों वाले बयान पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने आपत्ति जताई। तटकरे ने कहा कि अजित पवार 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में थे और उनका मानना था कि इससे राजनीतिक स्थिरता और बेहतर शासन संभव होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि एनसीपी, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। वहीं, पार्टी नेता सुरज चव्हाण ने बताया कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्र पवार को दोनों गुटों के विलय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

12 फरवरी को होना था औपचारिक विलय

शिंदे के अनुसार, 12 फरवरी को पार्टी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में दोनों गुटों के औपचारिक विलय का फैसला लिया जाना था। इतना ही नहीं, विलय के बाद एकीकृत एनसीपी की कमान अजित पवार को सौंपे जाने की योजना भी तय हो चुकी थी। लेकिन 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में अजित पवार के निधन के बाद यह प्रक्रिया अधूरी रह गई। शिंदे ने इसे किस्मत का हस्तक्षेप बताते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके सपने को पूरा करना चाहिए।

क्या होगा आगे?

अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं। यदि विलय की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। शशिकांत शिंदे ने अपने लेख के अंत में कहा कि अजित पवार को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि पार्टी एकजुट होकर मजबूत बने, वही पार्टी जिसे उन्होंने दशकों तक अपने परिश्रम से खड़ा किया।

2023 में क्यों टूटी थी एनसीपी?

गौरतलब है कि जुलाई 2023 में एनसीपी में बड़ा विभाजन हुआ था, जब अजित पवार ने तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। अजित पवार गुट को 'एनसीपी' नाम और 'घड़ी' चुनाव चिह्न मिला, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)' नाम दिया गया।

प्रत्यक्ष बिक्री क्षेत्र में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योग जगत को मिलकर करना होगा कार्य - अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर

'प्रत्यक्ष बिक्री के क्षेत्र में महाराष्ट्र देश में अग्रणी'; मुंबई में 'महाविकास-2026' संवाद सम्मेलन

सुरक्षित और पारदर्शी बाजार के निर्माण के लिए उपभोक्ताओं का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना तथा कंपनियों का उचित सेवाएं प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध होना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्यक्ष बिक्री (डायरेक्ट सेलिंग) क्षेत्र की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु सरकार और उद्योग क्षेत्र को मिलकर कार्य करना होगा– यह विचार अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) अनिल डिग्गीकर ने व्यक्त किए। मुंबई स्थित वाई. बी. चव्हाण केंद्र में 'महाविकास-2026' शीर्षक से एक विशेष संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन को सशक्त बनाने और प्रत्यक्ष बिक्री क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

IDSA की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के प्रत्यक्ष बिक्री क्षेत्र में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। राज्य का वार्षिक कारोबार 2,879 करोड़ रुपये है, जो देश के कुल बाजार हिस्से का 13 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में इस क्षेत्र से 10 लाख से अधिक प्रत्यक्ष विक्रेता जुड़े हुए हैं, जबकि देशभर में 39 लाख महिलाएं इस व्यवसाय में सक्रिय हैं। 'माविम' के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महाराष्ट्र में महिला उद्यमिता का उल्लेखनीय विस्तार हो रहा है।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर ने कहा, 'कानून और नियम तभी प्रभावी होते हैं, जब उनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर किया जाए। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और कंपनियों को अपने आचरण के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। यही संतुलन एक सुरक्षित और पारदर्शी बाजार का निर्माण करता है।'

मध्य रेलवे सोलापुर मंडल में रेल सप्ताह-2025 का भव्य आयोजन, 30 रेलकर्मियों एवं 9 विभागों को रेल सेवा पुरस्कार से सम्मान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल द्वारा 13 फरवरी 2026 को सिद्धेश्वर रेलवे अधिकारी क्लब के सभागार, सोलापुर में सत्तरवाँ रेल सप्ताह-2025 भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर सोलापुर मंडल के मंडलीय रेल प्रबंधक डॉ. सुजीत मिश्रा ने मंडल के रेलकर्मियों के अनुकरणीय, समर्पित एवं उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते हुए रेल सेवा पुरस्कार-2025 प्रदान किए। कार्यक्रम में 30 उत्कृष्ट रेलकर्मियों को व्यक्तिगत पुरस्कार तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 विभागों एवं डिपो को कार्यक्षमता शील्ड प्रदान की गई। इसके साथ ही मंडलीय स्तर पर विशेष रेल सेवा पुरस्कार-2025 के विजेताओं तथा दिनांक 9 फरवरी 2026 को संपन्न मंडलीय रेल प्रबंधक स्वच्छता निरीक्षण के विजेताओं का भी सम्मान किया गया।

व्यक्तिगत पुरस्कार विजेता इस प्रकार रहे–

लेखा विभाग से अमित कुमार, लेखा सहायक, सोलापुर।

सामान्य प्रशासन से योगेश कुमार, स्टेशन मास्टर, सोलापुर।

इंजीनियरिंग (स्थापत्य) विभाग से फुलचंद लक्ष्मण, वरिष्ठ तकनीशियन (राजमिस्त्री), शाहाबाद; रवि कुमार राजपाल सिंह, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (स्थायी मार्ग), सोलापुर; राहुल कृष्णा शिंदे, ट्रैक अनुरक्षक तृतीय, मोडनिंब; बालाजी बाबर, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (स्थायी मार्ग), बार्शी टाउन; लक्ष्मण सारंगधर रणदिवे, ट्रैक अनुरक्षक चतुर्थ, कुर्डुवाड़ी; विकास महादेव राठोड, ट्रैक अनुरक्षक तृतीय, होटगी; ओमप्रकाश बिजरनिया, कनिष्ठ अभियंता (स्थायी मार्ग), मोहोळ; तथा राजकुमार प्रसाद, ट्रैक अनुरक्षक तृतीय, बबलाद।

वाणिज्य विभाग से काले आनंद महादेव, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, कुर्डुवाड़ी तथा मोबीन शेख, टिकट निरीक्षक, सोलापुर।

यांत्रिक (कोच एवं वैगन) विभाग से मल्लिकार्जुन हंचप्पा, वरिष्ठ तकनीशियन, वाडी तथा चिंतामणी मोगे, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, पंढरपुर।

विद्युत (सामान्य) विभाग से मलप्पा अच्छिगर, सहायक ट्रैक्शन लाइन एवं वातानुकूलन, सोलापुर।

विद्युत (ट्रैक्शन वितरण) विभाग से एस. एच. मुलामणी, मुख्य लोको निरीक्षक, सोलापुर; आर. डी. कुलकर्णी, मुख्य लोको निरीक्षक, कुर्डुवाड़ी; प्रमोद नरटवडेकर, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, सोलापुर; तथा एंडेला महेश बाबू, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, दुधनी।

चिकित्सा विभाग से शिवेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य नर्सिंग पर्यवेक्षक, सोलापुर।

परिचालन विभाग से ठाकुर मुकेश कुमार, स्टेशन मास्टर, होटगी; सुनील कुमार सुमन, स्टेशन मास्टर, धाराशिव; अनिकेत सिंह, प्वाइंट्समैन श्रेणी बी, बाले; तथा दीनबंधु, स्टेशन प्रबंधक, सोलापुर।

कार्मिक विभाग से समाधान भरत कोळी, कार्यालय अधीक्षक, सोलापुर।

सुरक्षा विभाग से रितेश कुंभार, प्रधान आरक्षक, सोलापुर।

सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग से राशिद हमीद शियाख, तकनीशियन श्रेणी तृतीय (दूरसंचार), सोलापुर तथा सुहास माने, कनिष्ठ अभियंता (सिग्नल), पंढरपुर।

विद्युत (ट्रैक्शन वितरण) सुरक्षा से दुर्गाचरण नागले, वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, सोलापुर।

भंडार विभाग से अश्वनी राणा, डिपो सामग्री अधीक्षक, सोलापुर।

इंटर-डिपो कार्यक्षमता शील्ड विजेता–

वाणिज्य कार्यक्षमता शील्डः भारतीय तेल निगम साइडिंग, पाकणी।

परिचालन कार्यक्षमता शील्ड (सर्वश्रेष्ठ यार्ड)ः वाडी यार्ड।

परिचालन कार्यक्षमता शील्ड (सर्वश्रेष्ठ स्टेशन)ः वाशिंबे स्टेशन।

इंटर-डिपो कोच एवं वैगन शील्डः कोच एवं वैगन डिपो, सोलापुर।

सर्वश्रेष्ठ क्रू बुकिंग लॉबीः क्रू लॉबी, सोलापुर।

चिकित्सा विभागः रेलवे अस्पताल, वाडी।

विद्युत (सामान्य)ः विद्युत अनुरक्षण, सोलापुर।

विद्युत (ट्रैक्शन वितरण)ः ट्रैक्शन वितरण डिपो, केत्तूर।

सिग्नल एवं दूरसंचारः दूरसंचार डिपो, सोलापुर।

इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मंडलीय रेल प्रबंधक श्री अंशुमाली कुमार, केंद्रीय रेलवे महिला कल्याण संगठन सोलापुर के पदाधिकारी, शाखा अधिकारी, रेलवे यूनियन प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में रेलकर्मी उपस्थित रहे। रेल सप्ताह रेलकर्मियों के समर्पण, परिश्रम एवं उत्कृष्ट सेवा भावना के सम्मान का प्रतीक है और यह सोलापुर मंडल की यात्रियों तथा माल परिवहन ग्राहकों को सुरक्षित, कुशल एवं उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

सम्पादकीय

शब्दों का फेर या कूटनीतिक जीत? बाध्यकारी शर्तों से मुक्त हुआ भारत अमेरिका ने झुकाया रुख

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का अंतिम स्वरूप में पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच इसके अहम बिंदुओं के नफे-नुकसान के मसले पर जो बहस चल रही है, उसके असर भी सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के शुरुआती स्वरूप में कई अन्य अमेरिकी वस्तुओं सहित कुछ दालों पर भी भारत की ओर से शुल्क कम या समाप्त करने की खबर आई थी।

मगर भविष्य में भारतीय कृषि और किसानों पर इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई गई। अब अमेरिका की ओर से जारी नए तथ्य-पत्र में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं और कुछ शब्दों में भी बदलाव किया गया है। मसलन, समझौते के प्रारूप में पहले जहां भारत की ओर से पांच सौ अरब डालर से अधिक मूल्य के अमेरिकी उत्पाद खरीदने को 'प्रतिबद्धता' बताया गया था।

वहीं संशोधित संस्करण में इसे खरीदने के 'इरादे' के रूप में पेश किया गया है। यानी यह नियम अब भारत के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अलावा, संशोधन के बाद समझौते के प्रारूप में से कई कृषि वस्तुओं, खासकर दालों को इस सूची से बाहर करने की खबर है। इसके बाद स्वाभाविक ही भारतीय कृषि क्षेत्र में अमेरिका की ओर से खड़ी होने वाली प्रतिस्पर्धा से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यों भी, भारत दालों के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।

इसी वजह से खासतौर पर दालों को किसी भी व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा माना जाता रहा है। हाल ही में जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते में सहमति के स्तर तक पहुंचने की खबरें आई थीं, तब अमेरिका की ओर से शुल्क अठारह फीसद करने सहित इसके सकारात्मक पहलुओं की खासी चर्चा हुई थी। मगर कृषि तथा अन्य उत्पादों के संबंध में भारत के रुख को लेकर कई तरह की चिंता भी उभरी थी।

यह आशंका जताई गई कि अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं को भारत में निर्बाध छूट दी गई, तो यहां के कृषि क्षेत्र पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। इसीलिए किसानों की ओर से विरोध के स्वर भी उभरे। विपक्षी दलों ने भी ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया।

इन उतार-चढ़ावों के बीच व्यापार समझौते के प्रारूप में अब जिन बदलावों की खबर आई है, वह भारत के लिए सकारात्मक और राहत की बात साबित हो सकती है। इसमें कोई दोराय नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी साझेदारी कसौटी पर तभी उचित साबित हो सकती है, जब इसमें परस्पर और समान हित पर आधारित शर्तें शामिल हों। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मामले में अमेरिका और भारत की स्थिति को एक समान आधार पर नहीं देखा जा सकता।

इसलिए दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते में संतुलन के कारक संदर्भों पर निर्भर करेंगे। भारत अगर अमेरिकी उत्पादों के लिए अपना बाजार बिना कोई शर्त लगाए खोलता है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनके सामने प्रतिस्पर्धा एक चुनौती बन कर खड़ी हो सकती है। तमाम चिंता के बीच अमेरिका के साथ जारी बातचीत में भारत के कृषि क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी।

अब संशोधन के बाद अगर दोनों देशों के हित को सुनिश्चित करने वाली संतुलित नीतियां आकार ले पाती हैं, तब व्यापार समझौता भारत के लिए भी लाभकारी होगा। फिलहाल समझौते की शर्तों में अमेरिका की ओर से जो बदलाव किए गए हैं, वे अब आगे की वार्ता में एक संतुलनकारी भूमिका निभा सकते हैं।

तारिक की बीएनपी नहीं उस पार्टी का अब होगा शासन! जो नहीं चाहती थी की बांग्लादेश अलग मुल्क बने

बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। 2024 में शेख हसीना के जाने के बाद यह बांग्लादेश में होने वाला पहला चुनाव है। शेख हसीना जैसे आपको पहले भी पता है वहां पे जब हलचल हुई तो उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा। आवामी लीग बांग्लादेश में बैन है। क्योंकि ये कहा गया कि बांग्लादेश का युवा एक नया सिस्टम चाहता था। नया चेहरा चाहता था। लेकिन चुनावी मैदान में दो पुरानी पार्टियां ही अभी दिख रही हैं। बड़े प्लेयर्स के रूप में बीएनपी और जमात। बीएनपी के नेता तारिक उस राजनीतिक परिवार से हैं जिसने दशकों दशक बांग्लादेश की राजनीति पर गहरी पकड़ बनाकर रखी है। दूसरी तरफ हैं 67 साल के डॉ. शफीक उर रहमान। इनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। इन्होंने एक भी महिला उम्मीदवार को चुनाव में नहीं उतारा है। बांग्लादेश में आम चुनाव और जनमत संग्रह कई मायनों में ऐतिहासिक और असाधारण माने जा रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब इस पड़ोसी देश की पारंपरिक राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। दो दशकों तक सत्ता में रहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश से बाहर है और उनकी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक है। वहीं, बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की नेता और पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो चुका है। इन चुनावों में मौजूद 51 राजनीतिक दलों में मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है। इन दोनों ही दलों ने कई छोटे-छोटे दलों के साथ चुनावी गठजोड़ किए हैं। जमात-ए-इस्लामी 11 दलों के गठबंधन की अगुआई कर रही है। इसमें छात्र के समर्थन से बनी नैशनल सिटिजन पार्टी भी शामिल है, जो शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से निकली है। स्थानीय सर्वे में बीएनपी जीत

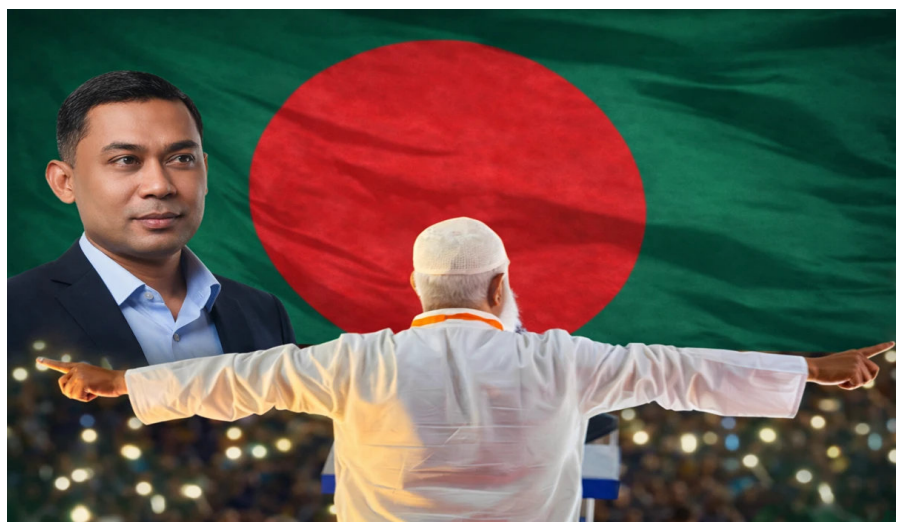

सकती है। हालांकि जमात को भी काफी लोकप्रिय बताया जा रहा है। 170 मिलियन 17 करोड़ की आबादी वाला ये देश 12 फरवरी को वोट देने वाला है। 300 सीटों पर चुनाव होगा और लगभग 2000 उम्मीदवार इन सीटों पर लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाबला काटे का है।

देश की राजधानी ढाका में 9 फरवरी को चुनावी माहौल पूरी पीक पर था अपने शहर में हजारों लोग झंडे लहराते हुए रैलियों में पहुंचे। हर पार्टी जनता के उस आंदोलन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही थी जिसने कभी शेख हसीना को राजनीति से बाहर किया। 17 साल के इंसाइल के बाद तारीख दिसंबर में देश लौटे हैं। उनके उनकी पार्टी के चुनावी वादे काफी स्ट्रेट हैं। जैसे गरीब परिवारों को पैसे की मदद देना, कोई भी नेता 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री ना रहे। ऐसी बात करना, विदेशी निवेश लाकर देश की इकॉनमी सुधारना और भ्रष्टाचार पर सख्ती। तारिक रहमान का कहना है कि सिर्फ बीएनपी के ही पास देश चलाने का एक्सपीरियंस है। रैलियों में अपने माता-पिता यानी जिया उर रहमान और खालिदा जिया का जिक्र कई बार किया यह कहते हुए कि दोनों ही देश चला चुके हैं और बाकी पार्टियों के पास ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है जो बीएनपी के पास है।

तारिक रहमान की पार्टी का सबसे बड़ा मुकाबला जमात इस्लामी से है। जमात इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है। इसके लीडर हैं शफीक उर रहमान। शफीक उर रहमान एक अलग तरह की राजनीतिक छवि रखते हैं। पेशे से सरकारी वो डॉक्टर रह चुके हैं और 2019 में उस वक्त जमात के चीफ बने थे जब पार्टी पर बैन था। दिसंबर 2022 में उन्हें रात के वक्त आतंकवाद से जुड़े इल्जामों में गिरफ्तार किया गया और 15 महीने बाद जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद मार्च 2025 में जब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बन गई तो उस केस से शफीक उर रहमान का नाम हटाया गया। इसके बाद से उनके भाषण और रैलियां लगातार सुर्खियों में रहते हैं। पिछले साल ढाका की एक बड़ी रैली में गर्मी के कारण मंच पर दो बार बेहोश हो गए थे। लेकिन डॉक्टरों की सलाह के बावजूद उठे और उन्होंने अपना भाषण पूरा किया। कहा जब तक अल्लाह मुझे जिंदगी देगा मैं लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। अगर जमात सत्ता में आई तो हम हुक्मरान नहीं जनता के सेवक होंगे। कोई मंत्री जमीन या टैक्स फ्री गाड़ी लेकर नहीं चलेगा। ना वसूली होगी ना भ्रष्टाचार। मैं युवाओं से साफ कहना चाहता हूं हम आपके साथ हैं। शेख हसीना के दौर में कई साल तक जमात पर बैन रहा। लेकिन 2024 में आंदोलन के बाद जब हसीना की सरकार गिर गई तो जमात फिर से पॉलिटिक्स में लौट आया। जमात के साथ नेशनल सिटीजन पार्टी है। इसे उन्हीं युवाओं ने बनाया है जिन्होंने हसीना को सत्ता से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

जमात ने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। पार्टी के बहुत से नेताओं को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के दौर में मुकदमा चलाने के बाद फांसी की सजा दी गई थी। हसीना के शासन में 2013 में पार्टी पर प्रतिबंध भी लगा कई सालों के बाद अब बाजी पलट गई है। राजनीतिक बदलाव जमात के पक्ष में है। पार्टी ने किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया है और देश का प्रगतिशील वर्ग काफी ज्यादा असहज है।

पूर्व में खालिदा की अगुआई वाली बीएनपी सरकार से भारत के रिश्ते बहुत सहज नहीं रहे। इस दल की कमान अब उनके बेटे तारिक रहमान के हाथ है, जिन्होंने लौटते ही 'समावेशी बांग्लादेश' का संदेश दिया था। खालिदा के अंतिम संस्कार में भारत से विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी से रिश्तों की नई झलक दिखी थी। लेकिन इनके मैनिफेस्टो में 'बांग्लादेश फर्स्ट के साथ पया तीस्ता नदियों के पानी के उचित हिस्से का उल्लेख आक्रामक रुख दिखाता है। वहीं, जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने भारत से संबंधों पर सांकेतिक जवाब दिया, जिसका अर्थ निकाला जा रहा है कि अगर उनका दल सत्ता में आता है, तो भारत के प्रति रुख में नरमी ही होगी।

संसदीय चुनाव की तरह जनमत संग्रह भी बैलट पेपर से होगा। सवैधानिक सुधारों से जुड़े बीती जुलाई के नैशनल चार्टर पर लोगों को 'हा' या 'ना' में जवाब देना है। अगर जनमत संग्रह पास हुआ तो नवनियुक्त ससद सविधान सभा की तरह काम करेगी और संविधान में बदलाव करेगी। चार्टर के तहत संसद में 100 सदस्यों का उच्च सदन भी बनेगा। पीएम के लिए दो कार्यकाल की सीमा (अधिकतम 10 साल) तय होगी। तटस्थ सरकार के तहत चुनाव कराने, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और भ्रष्टाचार विरोधी आयोग का भी प्रस्ताव है। यह सब पहले 270 दिनों में करना होगा।

अल्पसख्यकों पर हमलों और पाक से बढ़ती नजदीकी के बीच भारत के लिए बाग्लादेश बड़ी चुनौती से कम नहीं है। शेख हसीना के विरोध को भापने में नाकाम रहा भारत अब पहले से ही वहां सभी पक्षों से संपर्क में है। वहां का राजनीतिक नेतृत्व भी समझता है कि सामान्य संबंधों में ही सबका भला है।

संसद की गरिमा को बचाने की ज़रूरत

देश की संसद हमारे लोकतांत्रिक आचरण, संसदीय मर्यादाओं और संवाद की शुचिता का केंद्र होनी चाहिए। जहां संवाद से संकटों के हल खोजे जाएं। लेकिन पिछले दो दिनों में लोकसभा में जो हुआ, वह बहुत निराशाजनक है। सदन के नेता प्रधानमंत्री ही अगर अपने सदन को संबोधित न कर सकें, इससे ज्यादा निराश करने वाली बात क्या हो सकती है। ये हुआ , सबने देखा। यह संसदीय मर्यादाओं के तार-तार होने का भी समय है। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यह अपील करनी पड़ी कि प्रधानमंत्री लोकसभा में न आएं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब न दें। लोकसभा अध्यक्ष ने किस तरह की आशंकाओं के कारण ऐसा कहा होगा, इसे समझा जा सकता है।

इसके पहले सदन में हुए हंगामे, कागज फाड़कर आसंदी पर फेंकने जैसे दृश्य तो संसद ने अनेक बार देखे हैं। बावजूद इसके एक अभूतपूर्व दृश्य भी लोकसभा ने देखा जब लगभग सात महिला सांसद प्रधानमंत्री के आसन तक जा पहुंचीं। क्या हो सकता था, इसका अनुमान लगाना ठीक नहीं। किंतु बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने जो कुछ कहा वह बताता है, संसदीय मर्यादाओं की सीमाएं लांघते हुए हमारे सांसद दिखे। परंपरा रही है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब आमतौर पर प्रधानमंत्री देते हैं । इसकी न सिर्फ अपेक्षा रहती है बल्कि प्रतीक्षा भी आखिर सरकार के मुखिया क्या कहते हैं। स्थापित मान्यता यहां टूटती दिखी। प्रधानमंत्री लोकसभा को संबोधित नहीं कर सके। राज्यसभा में भी उनका भाषण विपक्ष की गैरमौजूदगी में हुआ। संसदीय लोकतंत्र में विरोध और संवाद साथ -साथ चलते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहले दिन से बहस और संवाद की संस्कृति को संरक्षित किया। वे यह चाहते थे अच्छे लोग संसद में आएं और संसदीय बहसों का स्तर ऊंचा हो। अपने विरोधी सांसदों की भी वे प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं।

दिग्गज सांसद राममनोहर लोहिया से लेकर युवा सांसद अटल बिहारी बाजपेई को भी उन्होंने ध्यान से सुना। यह परंपरा बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी बनाए रखी। विपक्ष भी अपने आचरण में मर्यादित रहा। संसद हमारे लोकतांत्रिक स्वभाव का आईना बनी रही। आपातकाल लागू होने के बाद क्षरण जरूर हुआ किन्तु बाद के दिनों में सब कुछ संभल गया। नरसिंहराव, चंद्रशेखर, अटलजी स्वयं बड़े संसदविद् थे और सदन गरिमा के साथ चलता रहा। कड़ी आलोचना के साथ , संवाद कायम रहा। पिछले कुछ समय से संवाद बंद है और कटुता बहुत बढ़ गई है। संसद शब्द की हिंसा का केंद्र बन गयी है। अपने सहयोगी सांसद को गद्दार की संज्ञा देना जैसे उदाहरण किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह शुभ नहीं है। यह सही बात है कि सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन विपक्षी दलों के सहयोग के बिना सदन नहीं चल सकता यह भी सच है। सदन में मिले विशेषाधिकार का लाभ लेकर सांसदों द्वारा हमारे महान दिवंगत नेताओं को कोसना , उनके जीवन के निजी पक्षों को किताबों के संदर्भ देकर उठाना कितना उचित है? इसके साथ ही बिना तथ्यों के किसी अनछपी किताब के उदाहरण से सरकार को घेरने की कोशिश भी बचकानी ही है। बजट सत्र संसद का बहुत महत्व का सत्र होता है।

जिसमें हम अपने देश के आगामी एक साल के सपनों, आकांक्षाओं, आर्थिक भविष्य का खाका खींचते हैं। ऐसे सत्र का समय नष्ट करके हमें क्या हासिल होगा, समझना मुश्किल है। मुद्दे की बात यह भी है कि क्या हमारे सांसद स्वस्थ बहस चाहते हैं? क्या क्षणिक राजनीतिक सुर्खियों के लिए हम समाज के वृहत्तर प्रश्नों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। दिवंगत नेताओं की चरित्रावली का वाचन करके हम कौन से मूल्य स्थापित कर रहे हैं? कभी नेता प्रतिपक्ष ने वीर सावरकर पर सवाल खड़े करके जो गलत परंपरा डाली , अब दूसरे सांसद बोरे में किताबें लाकर उनके अंश पढ़ रहे हैं। इससे हमें क्या हासिल होगा? नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल जी इस देश के महान नेता रहे हैं, उनके देहावसान के बाद ऐसी गलीज बातें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के बाद हम पुरखों के सद्गुण याद करते हैं। उनके प्रदेय और योगदान पर गर्व करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। किंतु हम किस रास्ते पर चल पड़े हैं? आजादी के इतने सालों बाद संसदीय बहस और संसदीय मर्यादाओं का स्तर ऊंचा करने के बजाय हम इसे रसातल में ले जा रहे हैं। कितना अच्छा होता कि हमारे सांसद यह समझ पाते कि देश की जनता ने उन्हें किन उम्मीदों से संसद में भेजा है। अगर सांसद ही तय लेंगे कि संसद नहीं चलेगी, तो उसे कौन चला सकता है। सांसद होना साधारण नहीं है, देश के 1 अरब, 40 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधियों का आचरण प्रश्नचिन्ह की तरह हमारे सामने है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी राजनीतिक दल ऐसे निराशाजनक दृश्यों से संसद को बचाने के लिए सोचेंगे। संसदीय राजनीति का यह पतन देखकर सबसे दुखी शायद पं.जवाहरलाल नेहरू और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही होते। दुर्भाग्यवश इन दोनों के राजनीतिक उत्तराधिकारी ही इन दृश्यों के लिए जिम्मेदार हैं। बाकी से क्या उम्मीद करना ?

यथार्थ और कल्पना में उलझा बचपन, आभासी दुनिया के जाल में उलझी पूरी पीढ़ी

हमारे देश में आज भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता कम ही नजर आती है। बच्चों की उदासी को नखरे, चुप्पी को जिद और चिड़चिड़ेपन को स्वभाव मानकर टाल दिया जाता है। बच्चों के साथ संवादहीनता तो और भी कई तरह के जोखिम पैदा कर सकती है।

ऐसे में बच्चों का अकेलापन उन्हें डिजिटल मंचों पर परोसी जा रही विभिन्न सामग्री की ओर आकर्षित करने लगता है। धीरे-धीरे वे आभासी दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि काल्पनिक और वास्तविकता के बीच अंतर को भी भूल जाते हैं।

विशेषकर आजकल स्मार्टफोन में जिस तरह के आनलाइन खेल परोसे जा रहे हैं, उनसे बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे आभासी दुनिया को ही असलियत समझने लगते हैं और कई बार आत्मघाती कदम तक उठाने को तैयार हो जाते हैं।

पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग इलाकों से कई ऐसी खबरें आईं, जिनमें स्मार्टफोन में किसी वीडियो गेम के असर में बच्चों ने जान गंवा दी या फिर गेम खेलने से मना किए जाने पर आत्मघाती कदम उठा लिया। कुछ वीडियो गेम ऐसे होते हैं, जिनकी बच्चों को लत लग जाती है और उसमें दिए जाने वाले जोखिम भरे लक्ष्य उनके लिए घातक साबित होते हैं।

भारतीय समाज में अधिकतर माता-पिता यह मान लेते हैं कि अगर उनका बच्चा स्मार्टफोन के साथ घर के किसी कमरे में है, तो वह सुरक्षित है। मगर उन्हें शायद इस बात का आभास नहीं होता है कि स्मार्टफोन के जरिए पूरी दुनिया उस कमरे में घुस आती है। यहीं नहीं, पढ़ाई, करिअर और अनुशासन पर जोर देते-देते कई बार बच्चों के साथ भावनात्मक संवाद भी छूट जाता है और यही चूक आगे चलकर जोखिमपूर्ण साबित हो सकती है।

ऐसे में जरूरत इस बात की है कि माता-पिता नियंत्रक नहीं, संवादक बनें। बच्चे दिनभर की अपनी गतिविधियों में क्या कर रहे हैं, क्या देख-सुन रहे हैं, यह जानना जरूरी है। अगर बच्चा स्मार्टफोन पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगे, तो उसके पीछे कारण को समझना भी अति आवश्यक है।

आजकल आभासी दुनिया में ऐसे कई तरह के खेल परोसे जा रहे हैं, जो बच्चों और किशोरों को आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाते हैं। शुरू में ये खेल बहुत रोचक होते हैं, जिस कारण बच्चा उनमें फंसता जाता है। ऐसे खेलों के प्रति बच्चों का झुकाव उनके भीतर पनप रहे अकेलेपन और उदासी की ओर इशारा करता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे संकेत लंबे समय से चल रहे मानसिक दबाव और भावनात्मक अलगाव का परिणाम होते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह के खेल में ज्यादा रुचि लेने लगे, तो धीरे-धीरे उसे आभासी दुनिया असल जिंदगी से ज्यादा 'वास्तविक' लगने लगती है।

इन संदर्भों ने एक बार फिर हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हम अपने बच्चों की बदलती दुनिया को सचमुच समझ पा रहे हैं? क्या हम उनसे इतना संवाद स्थापित कर रहे हैं कि वे बेझिझक अपने मन की उलझन हमसे साझा कर सकें?

आभासी दुनिया के खेलों के जाल में उलझे और लत का शिकार होकर गुम होते बच्चों की त्रासदी सिर्फ कुछ परिवारों से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि यह एक समूची पीढ़ी का संकट है, जो वास्तविक दुनिया से कटती जा रही है। जहां भावनाएं 'स्क्रीन' पर व्यक्त होती हैं, रिश्ते आभासी हो जाते हैं और पहचान 'एल्गोरिद्म' गढ़ते हैं। वह भी उम्र के बेहद नाजुक पड़ाव पर!

किशोरावस्था की बात की जाए, तो यह जीवन का वह दौर होता है, जहां भावनाएं तीव्र होती हैं, खुद की पहचान बन रही होती है और उस पहचान की स्वीकृति की भूख सबसे ज्यादा होती है।

इस उम्र में डांट, तिरस्कार या अचानक लगाया गया प्रतिबंध कई बार किशोरों द्वारा अनुशासन नहीं, बल्कि अस्वीकृति के रूप में ग्रहण किया जाता है। जब ऐसे समय में कोई किशोर खुद को घर, स्कूल या समाज में समझा हुआ महसूस नहीं करता, तो वह किसी ऐसे माध्यम की ओर आकर्षित होता है, जहां उसे लगे कि उसकी भावनाओं को यहां समझा जाएगा। भले ही वह माध्यम आनलाइन खेल, सोशल मीडिया मंच या कोई आभासी समुदाय ही क्यों न हो।

यह समझना बेहद जरूरी है कि आनलाइन खेल या डिजिटल सामग्री सीधे तौर पर आत्मघाती व्यवहार का कारण नहीं होते। उनकी ओर आकर्षित होना एक संकेत होता है; मन के भीतर चल रही बेचैनी का, जिसे बच्चा शब्दों में कह नहीं पाता।

जब आनलाइन खेल या आभासी दुनिया ही दोस्त, पहचान और भावनात्मक सहारा बन जाए, तब समस्या गहरी हो जाती है। वहां जीत-हार और आभासी सराहना असली जीवन की चुनौतियों से ज्यादा महत्त्वपूर्ण लगने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि बिना संवाद और समझ विकसित किए बगैर, बच्चों या किशोरों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर अचानक रोक लगा दी जाए, तो वे खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर सकते हैं।

हालांकि, आज के तकनीकी दौर और इस उम्र में आभासी दुनिया की सामग्री से प्रभावित होना स्वाभाविक है, मगर समस्या तब पैदा होती है, जब यह आकर्षण वास्तविक जीवन से पलायन का माध्यम बन जाता है। कुछ किशोर खुद को उस काल्पनिक दुनिया में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां भावनाएं सुंदर दिखती हैं, रिश्ते आदर्श लगते हैं और संघर्ष 'टास्क' दिखते हैं। धीरे-धीरे वास्तविक जीवन उन्हें कठोर, अस्वीकारात्मक और बोझिल लगने लगता है। यही प्रवृत्ति कई बार जोखिम में डाल देती है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों के लिए स्मार्ट फोन या लैपटाप के इस्तेमाल की समय सीमा निर्धारित की जाए। मगर, उनके साथ भावनात्मक समय बिताना, डांटने से पहले सुनना और रोकने से पहले समझना भी उतना ही जरूरी है। स्कूलों की भूमिका भी केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित नहीं रह सकती। आज जरूरत है कि स्कूलों में डिजिटल साक्षरता पर भी ध्यान दिया जाए।

बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि डिजिटल मंचों पर मौजूद तमाम सामग्री हमेशा सच या वास्तविकता नहीं होती। उनमें फर्क करने का विवेक बच्चों के भीतर विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षकों को भी यह समझने की जरूरत है कि किसी बच्चे का अक्सर चुप रहना, अलग-थलग रहना या पढ़ाई से कट जाना आलस्य नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहे संघर्ष के संकेत हो सकते हैं। आभासी दुनिया में बच्चों के लिए परोसी जा रही सामग्री में उम्र के अनुसार सुरक्षा, अभिभावकों की निगरानी और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनियां केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितनी ही प्राथमिकता देनी होगी। डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश केवल नियमों से नहीं, बल्कि संवाद और आपसी समझ से ही बेहतर हो सकती है। स्मार्टफोन बंद कराया जा सकता है, लेकिन मन नहीं। खेल हटाया जा सकता है, लेकिन अकेलापन तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि हम संवेदनशीलता को केंद्र में नहीं रखेंगे।

बच्चों की आनलाइन गतिविधियों पर सिर्फ निगरानी नहीं, बल्कि परस्पर संवाद और उनकी भावनाओं को समझना भी जरूरी है। जोखिम से भरे डिजिटल खेल की सामग्री को समझना और सलाह-मशविरा करना आवश्यक है। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह को सामान्य प्रक्रिया की तरह अपनाया जाना चाहिए।

जनपद में डिप्टी सीएम ने की स्वास्थ्य सेवाओ सघन समीक्षा

भारत माता प्रतिमा का किया अनावरण

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही।उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के जनपद भदोही आगमन पर हेलीपैड स्थल पर जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आगमन के पश्चात उप मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) सूरियावां का गहन निरीक्षण कर जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने वेटिंग हाल, इमरजेंसी, ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, एनबीएसयू एवं एसएनसीयू वार्डों का अवलोकन किया तथा मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार, दवा उपलब्धता एवं चिकित्सकीय व्यवहार की जानकारी ली। मरीजों द्वारा संतोषजनक सेवाएं मिलने की बात कही गई, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की।

सीएचसी में उपचार हेतु आई बुजुर्ग महिला कुसुम देवी एवं अन्य मरीजों से आत्मीय बातचीत करते हुए उन्होंने चिकित्सकों को शीघ्र जांच एवं समुचित उपचार के निर्देश दिए। इसी क्रम में अस्पताल में जन्मे नवजात शिशुओं को उप मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से जन्म प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

निरीक्षण उपरांत प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को बेहतर एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि गर्भवती महिलाओं का प्रसव सरकारी अस्पतालों में ही कराएं, जिससे जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। अस्पताल भवन की मरम्मत एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक धनराशि शासन स्तर से उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी दिया।

इसके पश्चात उप मुख्यमंत्री ग्राम चौगुना, सुरियावां (कठोर) स्थित सर्वशक्तिधाम मंदिर प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत माता की प्रतिमा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव एवं मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जो हमें एकता, अखण्डता और आत्मगौरव की प्रेरणा देती है।डिप्टी सीएम के आगमन के दृष्टिगत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।सीएचसी सुरियावां से लेकर सर्वशक्तिधाम चौगना तक चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहें।इस अवसर पर भारी संख्या में जनपद के जनप्रतिनिधिगण व जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे।

महाशिवरात्रि की तैयारियों के दृष्टिगत बड़े शिव मन्दिर का पुलिस अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं का किया स्थलीय निरीक्षण

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक, भदोही एवं प्रभात राय, क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर द्वारा संयुक्त रूप से आगामी महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुविधा, शांति व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत बड़े शिव मंदिर के आयोजकों से मिलकर तैयारियों की विस्तृत जानकारी की गयी एवं बड़े शिव मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया। जुलूस/दर्शनार्थियों के मार्ग में संभावित भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक बिंदुओं पर आयोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। आयोजकों को स्पष्ट हिदायत दी गई कि जुलूस के दौरान बड़े डीजे/उच्च ध्वनि वाले लाउडस्पीकर का उपयोग न किया जाए, ताकि स्थानीय निवासियों को असुविधा न हो तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित हो। आगामी पर्व महाशिवरात्रि एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत कस्बा गोपीगंज में पर्याप्त पुलिस बल के साथ सांयकालीन पैदल गश्त/भ्रमण किया गया।

पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जनपदवासियों से अपील की जाती है कि वे महाशिवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं उत्साहपूर्ण ढंग से मनाएँ। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने हेतु पुलिस प्रशासन पूर्ण सतर्क एवं सहयोग के लिए तत्पर है। आयोजकों एवं श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे पुलिस द्वारा दी गई सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें। आपातकालीन सहायता हेतु डायल-112 एवं स्थानीय पुलिस को सूचित करें। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का अफवाह/भ्रामक सूचना प्रसारित ना करें।

मेडल पहनाकर जिलाधिकारी ने सादान को किया सम्मानित

गोपीगंज। भदोही जिले के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों मे दर्ज कराने वाले गोपीगंज के सादान को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सम्मानित कर हौसला बढ़ाया, राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीत कर शानदार उपलब्धि हासिल करने पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सादान को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।जिलाधिकारी ने कहा कि मेहनत और लगन अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस मौके पर अध्यक्ष सुरेश सेठ, जनरल सेक्रेटरी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष आशीष सिंह मौजूद रहे।

बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क एडीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ की बैठक

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जनपद में 18 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, नकलविहीन और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में शुक्रवार कोएक बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा संचालन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। यह बैठक एडीएम (वित्त एवं प्रशासन) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर समय से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जाए। एडीएम ने बताया कि जनपद में कुल 94 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे व वॉयस रिकॉर्डर लगाए गए हैं, जिससे परीक्षा कक्ष की हर गतिविधि पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, नकल पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्टेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है।

प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ सम्पन्न कराई जाएंगी। इन पुख्ता तैयारियों से परीक्षार्थियों को भयमुक्त और अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षक संकुल बैठक, निपुण भारत मिशन का प्रमुख आधार : यशवंत सिंह

मंत्र भारत संवाददाता

सुरियावा। शुक्रवार प्रतिमाह निर्धारित एजेंडा पर होने वाली शिक्षक संकुल बैठकें निपुण भारत मिशन का प्रमुख आधार है।यह विचार तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सुरियावां यशवंत सिंह ने व्यक्त किया। एकेडमिक टीम सुरियावां के नेतृत्व में आयोजित इस तैयारी बैठक के मिनिट टू मिनिट स्टेप को ए आर पी देवेंद्र कुमार मिश्र ने साझा किया। एन बी एम सी पोर्टल के डाटा विश्लेषण के आधार पर ए आर पी मनोज प्रभाकर सिंह ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा किया। ए आर पी भास्करानंद मिश्र ने गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।संतोष कुमार और भैरवानंद यादव ए आर पी द्वारा टी ऐल एम के प्रयोग और महत्व के बारे में बताया गया।इस अवसर पर नोडल संकुल वेद प्रकाश रघुवंशी द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेज के बारे में विचार व्यक्त किया गया।नोडल संकुल भोलानाथ, नवनीत शुक्ल, प्रियंकर तिवारी, दिवाकर मिश्र, राकेश, दिनेश, सहित सभी शिक्षक संकुल बैठक में उपस्थित रहे।बैठक में एल एल एफ के ब्लॉक कॉर्डिनेटर लाल चंद ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया।बैठक का संचालन ए आर पी देवेन्द्र कुमार मिश्र ने किया।

महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल जनपद भदोही के पर्यवेक्षण में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनपद के सभी थानों द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । इस अभियान के अंतर्गत सभी थानों की एंटीरोमियो टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जानकारी दी गई, साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम व उनके अधिकारों की रक्षा एवं आत्मरक्षा के उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई । कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, बाल सहायता नंबर 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा म्बैम्स,दन.ग्ह पोर्टल की जानकारी देकर इन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया । कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही टेंप्लेट भी वितरित किए गए।

विकास खण्ड चायल में जनसुनवाई की अनदेखी पर स्पष्टीकरण तलब

कौशाम्बी। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने विकास खण्ड कार्यालय चायल का निरीक्षण किया और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान आईजीआरएस और जनशिकायत रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि शिकायतों के निस्तारण के बाद आख्या और शिकायतकर्ता से वार्ता का विवरण अंकित नहीं था। इस लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत से स्पष्टीकरण मांगा है। ज्ञात हो कि जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि जनसुनवाई सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए आईजीआरएस की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों को तत्काल पोर्टल पर अपलोड करने और कार्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय उपायुक्त मनरेगा मनोज वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की हुंकार, 'जेल भरो आंदोलन' की दी चेतावनी

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। बिजली विभाग के निजीकरण और केंद्र सरकार के प्रस्तावित 'इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल' के विरोध में जिले के विद्युत कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। भरवारी पावर हाउस पर 'विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति' के बैनर तले कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने से न केवल उनके भविष्य पर संकट आएगा, बल्कि आम जनता पर भी बिजली की कीमतों का भारी बोझ बढ़ेगा।

ज्ञात हो कि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघर्ष समिति के जिला संयोजक आदर्श केसरवानी ने कहा कि यदि सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया वापस नहीं ली या इसके लिए टेंडर जारी किया, तो प्रदेश भर के इंजीनियर और कर्मचारी सामूहिक रूप से 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संसद में बजट सत्र के दौरान बिजली

संशोधन बिल पारित करने की कोशिश की गई, तो देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी बिना किसी नोटिस के 'लाइटनिंग स्ट्राइक' यानी तत्काल कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। उनकी मुख्य मांगों में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेना, निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त करना और पुरानी पेंशन योजना (ध्झ्ए) को बहाल करना शामिल है।

इस प्रदर्शन के दौरान एसडीओ भरवारी के.एल. यादव, अवर अभियंता आशीष मौर्य, शिवमणि और ज्वाला बाबू समेत सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने संबोधन में कहा कि सरकार की नीतियां जनविरोधी हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन और तेज किया जाएगा।

सामूहिक विवाह योजना के तहत 91 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। सराय अकिल के भागवत एंड सुंदर रिसॉर्ट में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 91 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इन जोड़ों में 02 जोड़े मुस्लिम समुदाय के भी शामिल थे, जिनका निकाह उनकी परंपरा के अनुसार संपन्न कराया गया। अन्य जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूरा हुआ।

ज्ञात हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल, निवर्तमान विधायक संजय गुप्ता और मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने नवदम्पतियों को आशीर्वाद दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत प्रति जोड़ा 1 लाख रुपये का प्रावधान है, जिसमें 60 हजार रुपये कन्या के खाते में, 25 हजार का घरेलू सामान और 15 हजार आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। वक्ताओं ने इसे निर्धन परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी योजना बताया।

जिलाधिकारी ने मंझनपुर तहसील का किया औचक निरीक्षण

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने मंझनपुर तहसील का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी एसपी वर्मा को तहसील में फरियादियों के बैठने के लिए पर्याप्त इंतजाम, शुद्ध

पेयजल और शौचालयों की बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। पुरुष शौचालय में पानी की अनुपलब्धता और वाटर कूलर की गंदगी पर गहरी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित नाजिर का वेतन रोकने का आदेश दिया।

ज्ञात हो कि उप जिलाधिकारी न्यायालय के निरीक्षण में अभिलेख व्यवस्थित न मिलने पर पेशकार का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने राजस्व मामलों के निस्तारण में तेजी लाने और अभिलेखागार में सीसीटीवी की क्रियाशीलता बनाए रखने पर जोर दिया। लेखपालों और अमीनों की सर्विस बुक अपडेट रखने तथा 10 लाख से अधिक के बकायेदारों से वसूली तेज करने के निर्देश भी दिए गए। जनशिकायत रजिस्टर में शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर लिपिक को कड़ी चेतावनी दी गई।

नेवादा ब्लॉक निरीक्षणः अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। विकास खण्ड नेवादा के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने प्रशासनिक शिथिलता पर कड़ा रुख अपनाया। उपस्थिति रजिस्टर की जांच में सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), स्थापना लिपिक और ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के बिना सूचना अनुपस्थित मिलने पर उनका वेतन रोकने का आदेश दिया गया। साथ ही ब्लॉक के सभागार कक्ष में गंदगी पाए जाने पर खण्ड विकास अधिकारी को फटकार लगाई गई। आईजीआरएस रजिस्टर के रखरखाव में कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यालय के अभिलेखों को सुव्यवस्थित करने और परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी।

पत्रकार इश्तेयाक अहमद पर मुकदमे के विरोध में बढ़ा आक्रोश

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। जनपद में पत्रकार इश्तेयाक अहमद पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमे को लेकर पत्रकारों और सामाजिक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। विभिन्न पत्रकार संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए मुकदमा वापस लेने की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि सच लिखने की वजह से इश्तेयाक अहमद को निशाना बनाया गया है। उनका आरोप है कि बिना निष्पक्ष जांच के कार्रवाई कर दी गई, जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

ज्ञात हो कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए फर्जी मुकदमा वापस लेने और पत्रकार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान 'इश्तेयाक अहमद को न्याय दो, फर्जी मुकदमा वापस लो' और 'कलम की आवाज़ दबेगी नहीं' जैसे नारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है और यदि पत्रकारों को ही प्रताड़ित किया जाएगा तो जनहित के मुद्दे सामने नहीं आ पाएंगे। पत्रकार संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

उद्योग बंधु की बैठक : बैंक ऋण आवेदनों के निस्तारण के निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में उदयन सभागार में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उद्यमियों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए गए। सीडीओ ने 'सीएम उद्यमी युवा योजना' के तहत बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों की समीक्षा की और बैंकर्स को फरवरी माह के भीतर सभी लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए।

ज्ञात हो कि उपायुक्त उद्योग ने बैठक में बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त 1580 प्रकरणों में से 1371 का निस्तारण हो चुका है। शेष 28 लंबित प्रकरणों, जो कृषि, श्रम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे विभागों से संबंधित हैं, उन्हें तत्काल क्लियर करने को कहा गया। बैठक में सीएमओ डॉ. संजय कुमार सहित प्रमुख उद्यमी रमेश अग्रहरी और प्रवेश केसरवानी मौजूद रहे।

एनीमिया मुक्त समाज के लिए मेडिकल कॉलेज ने चलाया जागरूकता अभियान

कौशाम्बी। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की ओर से विश्व एनीमिया जागरूकता दिवस और डी-वॉर्मिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. हरिओम कुमार सिंह ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद कादीपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कैंप लगाकर छात्र-छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। विशेषज्ञों ने बताया कि एनीमिया बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करता है। डॉ. रविरंजन सिंह और डॉ. संतोष कुमार ने छात्रों को आयरन युक्त आहार, हरी सब्जियां और स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी। विद्यालय में बच्चों को कृमिनाशक (डी-वॉर्मिंग) दवाएं भी दी गईं ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

भिवंडी में सांडपानी पर पूर्ण प्रक्रिया की तैयारी

नई परियोजना से 112 एमएलडी तक बढ़ेगी क्षमता- आयुक्त

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सांडपानी (सीवेज) के पूर्ण उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मनपा आयुक्त के अनुसार भुयारी गटर योजना (अंडरग्राउंड सीवरेज) के दूसरे चरण के तहत बनाए गए पंपिंग स्टेशन और मलशुद्धीकरण केंद्र पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद शहर में बनने वाले अधिकांश सांडपानी पर प्रभावी प्रक्रिया संभव हो सकेगी।

मनपा प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में भिवंडी शहर को स्टेम प्राधिकरण से 73 एमएलडी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका से 42 एमएलडी और मनपा के वाराला तालाब से 5 एमएलडी सहित कुल 120 एमएलडी प्रतिदिन पानी की आपूर्ति होती है। इस जल आपूर्ति से प्रतिदिन लगभग 90 एमएलडी सांडपानी का निर्माण होता है। फिलहाल 43 एमएलडी क्षमता वाली सांडपानी प्रक्रिया प्रणाली कार्यरत है, जिसके माध्यम से लगभग 30 एमएलडी सांडपानी का उपचार किया जा रहा है। मनपा कार्यक्षेत्र में भुयारी गटर योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत कुल सात पंपिंग स्टेशन और चार मलशुद्धीकरण केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों का ट्रायल रन वर्तमान में जारी है। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना पूरी तरह शुरू होने के बाद शहर में सांडपानी उपचार की कुल क्षमता बढ़कर 112 एमएलडी प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी, जिससे शहर से निकलने वाले लगभग सभी सांडपानी पर पूर्ण प्रक्रिया संभव हो सकेगी। मनपा आयुक्त ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जल प्रदूषण में कमी आएगी और शहर की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी।

रोज 20 घंटे फोन पर बिताती थीं गाजियाबाद में सुसाइड करने वाली तीनों बहनें, डाटा ने खोल दी सारी पोल

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों की कथित आत्महत्या की जांच के दौरान पुलिस को एक अहम डिजिटल सुराग मिला है। फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे गए मोबाइल फोन से बरामद डेटा में सामने आया है कि बहनें कथित तौर पर रोज़ाना लगभग 20 घंटे कोरियन कंटेंट, कार्टून और गेमिंग सामग्री देखती थीं। पुलिस इस डिजिटल पैटर्न को केस के मनोवैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य पहलुओं से जोड़कर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, 16, 14 और 12 वर्ष की तीनों बहनों ने 4 फरवरी को सोसायटी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। जांच में पता चला कि उनके पिता चेतन कुमार ने घटना से करीब 15 दिन पहले लड़कियों का मोबाइल फोन शालीमार गार्डन स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को 15, 000 रुपये में बेचा था। बाद में इस डिवाइस को डिलीट डेटा रिकवर करने और ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल के लिए फोरेंसिक जांच में शामिल किया गया।

एक जांच अधिकारी ने बताया कि रिकवर किए गए डेटा से यह समझने में मदद मिली कि बहनें इंटरनेट पर क्या देख रही थीं और क्या वे परिवार के बाहर किसी के संपर्क में थीं। अब तक के विश्लेषण में बहनों की कोरियन कल्चर, खासकर के-पॉप, में गहरी रुचि सामने आई है। सुसाइड नोट में

उल्लिखित गेम्स से संबंधित सामग्री भी फोन में पाई गई, जिनमें हॉरर टाइटल्स जैसे पोपी प्लेटाइम, द बेबी इन येलो, आइस स्क्रीम, ईविल नन और आइस गेम शामिल हैं।

पुलिस ने इन पांच गेम्स को लेकर सरकार को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें संभावित प्रतिबंध की सिफारिश की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है, ताकि किशोरों पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जा सके।

भिवंडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई में चार गिरफ्ता

नकली पुलिस बनकर करते थे लूट

10.75 लाख का माल बरामद

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और नकली पुलिस बनकर लोगों को लूटने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दो पेशेवर लुटेरों और चोरी का माल खरीदने वाले दो आरोपियों समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार आरोपियों पर 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। क्राइम ब्रांच द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त अमरसिंह जाधव ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से करीब 10 लाख 75 हजार रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई।

नकली पुलिस बनकर बनाते थे शिकार.....

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग के अलावा नकली पुलिसकर्मी बनकर राहगीरों को रोकते और उनके कीमती सामान लूट लेते थे। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने कबूल किया कि चोरी का माल कल्याण निवासी दिनेश पांडुरंग पाटिल को बेचने के लिए दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों में भिवंडी निवासी रविंद्र धनाजी भोसले और पुणे निवासी मोहम्मद अजीज जाफरी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, मोहम्मद अजीज जाफरी भिवंडी शहर महामार्ग पर नकली पुलिस बनकर वारदातों को अंजाम देता था। उसने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि लूटे गए आभूषण कर्नाटक निवासी श्रीकांत रामचंद्र गवले को बेचे गए थे।

गुप्त सूचना और तकनीकी जांच से मिली सफलता.....

क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत को मिली गुप्त सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने भिवंडी के नारपोली क्षेत्र से रविंद्र भोसले को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी को कल्याण-भिवंडी बाईपास के पास जाल बिछाकर पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने भिवंडी, कल्याण, ठाणे, उल्हासनगर, कर्जत रेलवे और पुणे रेलवे क्षेत्र में चेन स्नैचिंग के 18 और मोबाइल स्नैचिंग के 3 मामलों को कबूल किया है। पुलिस अन्य संभावित मामलों की भी जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई को क्षेत्र में बढ़ती स्नैचिंग घटनाओं पर बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है।

भिवंडी में महापौर की कुर्सी पर सस्पेंस बरकरार, सत्ता की चाबी किसके पास

'किंगमेकर' की भूमिका में विलास पाटील, 20 फरवरी को होगा बड़ा फैसला

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव एक साथ संपन्न होने के बाद अधिकांश महानगर व नगर पालिकाओं में महापौर का चयन हो चुका है, लेकिन भिवंडी महानगरपालिका में अब तक सत्ता का गणित उलझा हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण महापौर पद को लेकर सियासी हलचल चरम पर पहुंच गई है। शहर के राजनीतिक गलियारों से लेकर आम नागरिकों तक एक ही सवाल चर्चा में है–आखिर भिवंडी का अगला महापौर कौन होगा ?.

कोकण आयुक्त द्वारा आगामी 20 फरवरी को महापौर और उपमहापौर पद के चुनाव के निर्देश जारी होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों के नगरसेवक समर्थन जुटाने और संभावित गठबंधन बनाने में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

हाल ही में शिवसेना के वरिष्ठ नगरसेवक मनोज काटेकर की गटनेता पद पर नियुक्ति ने राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि

यह कदम महापौर पद की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी दल ने आधिकारिक रूप से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन काटेकर का नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल माना जा रहा है। इसके आलावा पूर्व महापौर विलास पाटील का नाम मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में अहम माना जा रहा है। बहुमत के अभाव में विभिन्न दलों के बीच समर्थन जुटाने की कवायद जारी है और इस स्थिति में पाटील की भूमिका निर्णायक हो सकती है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कई नगरसेवक उनके रुख पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि महापौर चुनाव में वे 'किंगमेकर' की भूमिका निभा सकते हैं।

राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक शिवसेना (12), कांग्रेस (30), कोणार्क विकास आघाड़ी (5) और भिवंडी विकास आघाड़ी (3) के संभावित समर्थन से संख्या 50 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के 6 नगरसेवकों के भी इस समीकरण में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह गठबंधन आकार लेता है तो सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि राज्य में नगर विकास विभाग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास होने के कारण विकास के मुद्दे पर दलों के बीच सहमति बन सकती है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा शिवसेना को महापौर पद के लिए समर्थन देने की संभावनाओं को भी राजनीतिक विश्लेषक नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। भिवंडी के नागरिक लंबे समय से नए महापौर के चयन का इंतजार कर रहे हैं। अब 20 फरवरी को होने वाले चुनाव के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शहर की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। फिलहाल राजनीतिक जोड़-तोड़ और रणनीतिक बैठकों का दौर जारी है, जिससे शहर का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है।

काल्हेर खाड़ी में अवैध रेती माफिया पर बड़ी कार्रवाई

पोकलेन-डंपर सहित 97 लाख का माल जब्त

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी तालुका के काल्हेर खाड़ीपात्र में चल रहे अवैध रेती उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेती माफियाओं को जोरदार झटका दिया है। ठाणे जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में पोकलेन मशीन, हायवा वाहन और बड़ी मात्रा में अवैध रेती सहित करीब 97 लाख रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है।

गौरतलब हो कि उल्हास नदी की खाड़ी में बड़े पैमाने पर अवैध रेती उत्खनन की शिकायत मिलने के बाद ठाणे के जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अपर जिल्हाधिकारी हरिचंद्र पाटील, उपजिल्हाधिकारी रूपाली भालके और उपविभागीय अधिकारी अमित सानप के मार्गदर्शन में जिला खनिकर्म अधिकारी विवेक घुले, रेतीगट तहसीलदार अमोल कदम तथा भिवंडी तहसीलदार अभिजित खोले के नेतृत्व में संयुक्त दक्षता पथक ने काल्हेर रेती बंदर पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान टीम को 19 अवैध रेती साठे मिले, जिनमें करीब 1523 ब्रास रेती जमा पाई गई। रेती उपसा में इस्तेमाल होने वाला एक हायवा वाहन और पोकलेन मशीन जब्त की गई। इसके अलावा अवैध रेती संग्रह के लिए बनाई गई छह बड़ी कुंडियों को पोकलेन की मदद से नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह पूरा मुद्देमाल करीब 97 लाख रुपये का है। इस धड़क कार्रवाई के बाद रेती माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन का कहना है कि काल्हेर बंदर क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन और रेती साठवणूक की गतिविधियां चल रही थीं। राजस्व विभाग की यह लगातार चौथी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मामले में रेती माफियाओं के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भिवंडी मनपा में सत्ता का महासंग्राम, 20 फरवरी को तय होगी महापौर-उपमहापौर की कुर्सी

तेज हुई राजनीतिक हलचल

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में सत्ता के नए समीकरणों को लेकर सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। नगर सचिव द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार आगामी 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को दोपहर 12 बजे मनपा मुख्यालय के सभागृह में विशेष सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें अगले ढाई वर्षों के कार्यकाल के लिए नए महापौर और उपमहापौर का चुनाव किया जाएगा। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 19(1) के तहत यह विशेष बैठक बुलाई गई है। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक उम्मीदवारों को 16 फरवरी 2026 को दोपहर 3 से 5 बजे के बीच नगर सचिव के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। 20 फरवरी को सभा के प्रारंभ में ही पीठासीन अधिकारी एवं ठाणे जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाल नामांकन पत्रों की जांच करेंगे और वैध उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। नियमानुसार उम्मीदवारों को 15 मिनट के भीतर नाम वापस लेने का अवसर मिलेगा।इसके बाद मतदान की प्रक्रिया हाथ उठाकर पूरी की जाएगी। यदि किसी स्थिति में दो उम्मीदवारों को समान मत मिलते हैं, तो विजेता का फैसला लॉटरी पद्धति से

किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह चुनाव भिवंडी की आगामी राजनीति और विकास की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और सत्ता समीकरणों को लेकर जोड़-तोड़ की राजनीति तेज हो गई है। शहर की नजरें अब 20 फरवरी की इस अहम बैठक पर टिकी है क्योंकि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। 90 सीटों वाली मनपा में कांग्रेस पार्टी के 30, भाजपा 22,राकांपा (शरद पवार) 12, शिवसेना (शिंदे) 12, समाजवादी 06,कोर्णाक विकास आघाडी 06, भिवंडी विकास आघाडी (एकता मंच) 03 और अपक्ष 01 सीट पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस, राकांपा व समाजवादी सेकुलर फ्रंट बनाकर महापौर बनाने की दावा की है। जबकि इस खेमे समाजवादी के 6 नगरसेवक सेकुय फ्रंट छोड़कर खिसक लिए है। वही पर भाजपा में अंतरकलह होने से सुमित पास पाटिल व नारायण चौधरी दो लोगों ने महापौर पद के लिए दावा किया है।

गुम नहीं 'गिरफ्तार' हुए सपा प्रवक्ता बाराबंकी पुलिस ने मनोज यादव को दबोचा

तिलक समारोह से गायब होने का खुला राज!

लखनऊ **(एजेंसी)**। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को लेकर पिछले 48 घंटों से चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। जिसे लखनऊ पुलिस और परिजन 'लापता' समझकर तलाश रहे थे, उन्हें बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोज यादव को उनके साथियों के साथ सफदरगंज इलाके से हिरासत में लिया गया।

मनोज यादव मंगलवार को काकोरी में एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। वहां से निकलने के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और वे घर नहीं पहुंचे। परेशान परिवार ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस सीसीटीवी और लोकेशन खंगाल रही थी, तभी बाराबंकी पुलिस की इस कार्रवाई ने सबको चौंका दिया।

बाराबंकी पुलिस के अनुसार, मनोज यादव उर्फ बबलू के खिलाफ सफदरगंज थाने में 11 फरवरी को एक मुकदमा (मु0अ0सं0 50/26) दर्ज हुआ था। उन पर आरोप है कि उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जान से मारने की धमकी दी। पुलिस इसी मामले में उनकी तलाश कर रही थी और बुधवार को उन्हें सफदरगंज इलाके से दबोच लिया गया।

गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मनोज यादव का बड़ागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके तुरंत बाद पुलिस की एक विशेष टीम उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ लेकर रवाना हो गई।

धूल चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा... सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि उनके व्यवहार से बेटियां घबरा गईं और व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। उन्होंने अपनी आलोचना को प्रसिद्ध कवि मिर्ज़ा ग़ालिब के एक कथन से समाप्त किया, 'धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ़ करता रहा,' जिसका अर्थ है कि विपक्ष अपनी गहरी विफलताओं के लिए दूसरों को दोष दे रहा है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने राज्य को शर्मिंदा किया, और दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले आठ वर्षों में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि राज्य की छवि अचानक खराब नहीं हुई। यह समाजवादी पार्टी का विशेष व्यवहार था जिसने बेटियों को घबरा दिया

और व्यापारियों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। विपक्ष के भाषण का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। और ग़ालिब ने कहा था, 'उमर भर मैं यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ़ करता रहा।' इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी ने दावा किया कि नीति आयोग के आंकड़ों पर आधारित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने पिछले 8 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी की रेखा से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अन्य योजनाओं से वंचित किया जाए। उन्हें राशन, स्वास्थ्य और अन्य सभी प्रशासनिक सुविधाएं मिलती रहेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भाषण के साथ शुरू हुआ, जिसमें विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की। अपने भाषण में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

बजट सत्र 9 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा, और 2026-27 वित्तीय वर्ष का राज्य बजट 11 फरवरी को पेश किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 2025 के महाकुंभ में 65 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे, और प्रयागराज में आयोजित 2026 के माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक लोग शामिल हुए थे। सत्र से पहले, समाजवादी पार्टी (एसपी) के विधायक रविदास मेहरोत्रा ??ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल को सरकार के दावों को दोहराने के बजाय अपना भाषण देना चाहिए और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पार्टी इसका विरोध करेगी।

पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का 'स्पिन चक्रव्यूह' तैयार, वरुण चक्रवर्ती बोले- हम उन्हें मात देंगे

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे ग्रुप चरण के मैच में नामीबिया को 93 रनों से हराने के बाद, भारत रविवार को कोलंबो में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अगले मैच की तैयारी में जुट गया है। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भारत की स्पिन गेंदबाजी पर भरोसा जताया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनकी टीम पड़ोसी देश पाकिस्तान से बेहतर है। जियोहॉटस्टार के 'मैच सेंटर लाइव' पर बोलते हुए चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे पास एक मजबूत स्पिन आक्रमण है और मुझे लगता है कि हम उनसे बेहतर हैं। वे लगातार इन्हीं परिस्थितियों में खेल रहे हैं, इसलिए उन्हें शायद इन परिस्थितियों से परिचित होने का फायदा मिल सकता है। लेकिन एक टीम के रूप में, हमने उन्हें मात दी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं।

वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि विश्व कप में जब भी आप किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलते हैं, तो आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होता है। आपको यह मानना होगा

कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं; तभी आप महत्वपूर्ण क्षणों में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए, भारत ने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के विस्फोटक अर्धशतकों की बदौलत 209/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया। किशन ने महज 24 गेंदों में 61 रन बनाए, जबकि पांड्या ने 28 गेंदों में 52 रन बनाए। नामीबिया के कप्तान गेरार्ड इरास्मस ने चार विकेट लेकर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा, लेकिन भारत के आक्रामक मध्यक्रम के आक्रमण ने इस विशाल स्कोर को सुनिश्चित कर दिया।

नामीबिया ने सकारात्मक शुरुआत करते हुए पावरप्ले के अंत तक 57/1 रन बनाए और कुछ समय के लिए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। हालांकि, स्पिनरों के आने के बाद मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। वरुण चक्रवर्ती ने निर्णायक गेंदबाजी करते हुए दो ओवरों में 3/7 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल (2/20) और हार्दिक पांड्या (2/21) ने भी गेंदबाजी में कसी हुई गेंदबाजी का इस्तेमाल किया। अंततः नामीबिया 18.2 ओवरों में 116 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे भारत को एक व्यापक जीत मिली।

भारत की शानदार जीत के बाद अपने दृष्टिकोण पर विचार करते हुए चक्रवर्ती ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुझे अपनी लय वापस पाने का मौका नहीं मिलता। मुझे पहली ही गेंद से लय में रहना होगा। मैं इस पर लंबे समय से काम कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली गेंद आसान हो। पहली गेंद से ही मुझे सटीक निशाना लगाना होगा।

टी20 वर्ल्ड कप : मोहम्मद आमिर का अभिषेक शर्मा पर तीखा हमला, आउट करने की योजना भी बता गए

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले माहौल गरमा गया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज़ मोहम्मद आमिर ने भारतीय सलामी बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी शैली पर सवाल उठाए हैं। आमिर का कहना है कि अभिषेक आक्रामक तो हैं, लेकिन तकनीकी रूप से मजबूत नहीं। खास बात यह है कि ये बयान 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान ग्रुप मैच से ठीक पहले आए हैं, जिससे मुकाबले का रोमांच और बढ़ गया है।

एक पाकिस्तानी टीवी कार्यक्रम में बातचीत के दौरान आमिर ने कहा कि अभिषेक की बल्लेबाजी हाई-रिस्क पर आधारित है। उनके मुताबिक, वह लगभग हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं जिससे उनके आउट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आमिर का मानना है कि अभिषेक की पारियां निरंतर नहीं रही हैं। उन्होंने संकेत दिया कि कई मैचों में छोटी

पारियों के बाद एक बड़ी पारी आती है, लेकिन यह स्थिरता नहीं दर्शाती। आमिर ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी नजर में अभिषेक तकनीकी रूप से परिपक्व बल्लेबाज नहीं हैं।

आमिर ने सिर्फ आलोचना ही नहीं की, बल्कि अभिषेक को आउट करने की योजना भी साझा की। उनका सुझाव था कि डीप कवर पर फील्डर तैनात कर शरीर की लाइन पर गेंदबाजी की जाए। इसके अलावा, उन्होंने धीमी गति की गेंदों (स्लोअर डिलीवरी) को प्रभावी हथियार बताया। कोलंबो में खेले जाने वाले इस हाई-वोल्टेज मैच में आमिर के अनुसार यही रणनीति भारतीय बल्लेबाज़ को फंसाने में कारगर हो सकती है।

भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले एक और चिंता की बात यह है कि अभिषेक फिलहाल अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। यदि वह फिट नहीं हो पाते, तो टीम संयोजन पर असर पड़ सकता है। ऐसे में उनकी उपलब्धता पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

अभिषेक पहले भी स्वीकार कर चुके हैं कि तेज गेंदबाज उनके खिलाफ गति कम रखते हैं और विविधताओं का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाफ हालिया सीरीज के दौरान उन्होंने कहा था कि वह संभावित रणनीतियों को ध्यान में रखकर अभ्यास करते हैं। उनका मानना है कि अगर आक्रामक क्रिकेट खेलना है, तो हर तरह की गेंदबाज़ी के लिए तैयार रहना होगा।

100-500 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा अपडेट, आरबीआई ने किया ऐलान!

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 100 और 500 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इन दोनों करेंसी नोटों की सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला किया है। जल्द ही बाजार में नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ अपडेटेड नोट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, सबसे राहत की बात यह है कि पुराने 100 और 500 रुपए के नोट फिलहाल पूरी तरह वैध रहेंगे और उन्हें बंद करने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे व्यापार और रोजमर्रा के लेनदेन में नकद का इस्तेमाल अभी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में नकली नोटों पर रोक लगाने और नोटों की लाइफ बढ़ाने के लिए सुरक्षा फीचर्स को अपग्रेड करना जरूरी हो गया है। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक भी अपनी करेंसी को समय-समय पर बेहतर बना रहे हैं।

100 रुपए के नोट में कोई बड़ा डिजाइन बदलाव नहीं किया गया है लेकिन इसकी स्याही, प्रिंट क्वालिटी और कंट्रास्ट को बेहतर बनाया गया है। वॉटरमार्क और सुरक्षा धागे को और स्पष्ट किया गया है, जिससे असली और नकली नोट की पहचान आसान होगी। नोट की मजबूती भी बढ़ाई गई है ताकि ज्यादा इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब न हो। नया नोट दिखने में लगभग पहले जैसा ही रहेगा लेकिन बारीकियां और टच फीचर्स ज्यादा स्पष्ट होंगे।

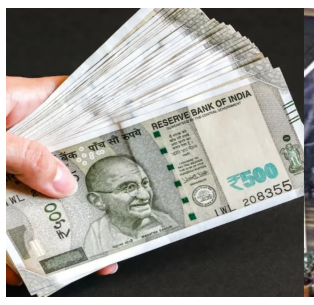

500 रुपए के नोट की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होने के कारण नकली नोट बनाने वालों का फोकस इसी पर रहता है। माइक्रो-प्रिंटिंग, रंगों की एकरूपता और डिजाइन एलिमेंट्स को बेहतर बनाया गया है। हालांकि, नोट का मूल ढांचा पहले जैसा ही रहेगा ताकि लोगों को पहचान में दिक्कत न हो।

डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर चेन्नई रोमांचक मुकाबले में जीते मनुष-दीया मिश्रित युगल क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत के मानुष शाह और दीया चिताले की शीर्ष मिश्रित युगल जोड़ी तथा युवा खिलाड़ी अंकुर भट्टाचार्जी ने बृहस्पतिवार को यहां डब्ल्यूटीटी स्टार कंटेंडर चेन्नई 2026 में अलग-अलग अंदाज में जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। हाल में डब्ल्यूटीटी कंटेंडर मस्कट 2026 का खिताब जीतने वाली मानुष और दीया की जोड़ी को कोरियाई क्वालीफायर खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर दी।भारतीय जोड़ी ने 42 मिनट में 3-2 (10-12, 11-6, 12-10, 5-11, 12-10) से जीत दर्ज कर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई।

मनुष और दीया का सामना भारतीय वाइल्ड कार्ड जोड़ी पायस जैन और सिंड्रेला दास से होगा। पायस और सिंड्रेला ने पहले दौर में कजाखस्तान के इस्केंडर खार्की और सर्विनोज मिर्कादिरोवा को 11-8, 11-6, 11-7 से हराया। क्वालीफायर अंकुर ने फ्रांस के फ्लोरियन बुरासो को 3-1 (11-5, 11-8, 3-11, 11-9) से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरे दौर में उनका सामना जापान के 14वीं वरीयता प्राप्त काजुहिरो योशिमुरा से होगा। अंकुर ने स्वस्तिका घोष के साथ मिलकर मिश्रित युगल क्वार्टरफाइनल में भी जगह बनाई। इस जोड़ी ने कोरिया के पार्क ग्युह्योन और किम नायोंग को 3-2 (11-9, 3-11, 11-8, 6-11, 11-9) से हराया। अब उनका मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े से होगा जिन्होंने रोमानिया के डेरियस मोविलेनू और एंड्रिया ड्रैगोमन को 11-8, 11-4, 11-7 से पराजित किया।

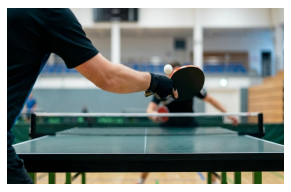

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ाने के लिए एफटीए का बेहतर फायदा उठाना जरूरी : नीति आयोग रिपोर्ट

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ाने के लिए संरचनात्मक लागत संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का बेहतर ढंग से फायदा उठाना और रणनीतिक कलपुर्जों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है। आयोग की शुक्रवार को जारी 'ट्रेड वॉच क्वार्टरली' रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का दुनियाभर में 4.6 लाख करोड़ डॉलर का बाजार है, लेकिन 2024 में भारत की हिस्सेदारी लगभग एक प्रतिशत ही रही। कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च-प्रौद्योगिकी कलपुर्जों के बाजार पर चीन, हांगकांग और ताइवान का दबदबा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल में कई देशों एवं समूहों के साथ हुए एफटीए से भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजार तक पहुंच बेहतर हुई है लेकिन अस्थिर भू-राजनीतिक माहौल में निवेश जुटाने के लिए घरेलू खरीद नीति में अनुमान लगा पाने की क्षमता, निर्यात वित्त और विनियामक सरलीकरण पर अधिक जोर देना होगा। नीति आयोग ने सुझाव दिया कि भारत की रणनीति को असेंबली आधारित वृद्धि से आगे बढ़कर कलपुर्जा-आधारित विनिर्माण की ओर स्थानांतरित होना चाहिए। आपूर्ति पक्ष पर प्रोत्साहनों को घरेलू मूल्य संवर्धन, निरंतर शोध एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने वाले 'एंकर निवेश' से जोड़ा जाना चाहिए।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात मुख्यतः अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एवं नीदरलैंड को होते हैं और इनमें मोबाइल फोन की हिस्सेदारी 52.5 प्रतिशत है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में इंटीग्रेटेड सर्किट, मोबाइल फोन और डेटा प्रोसेसिंग मशीनों की बड़ी हिस्सेदारी है। सितंबर तिमाही में देश के कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात में लगभग 8.5 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई, जो आयात वृद्धि से अधिक रही। रिपोर्ट के मुताबिक, सीमापार ई-कॉमर्स 2030 तक निर्यात वृद्धि का प्रमुख माध्यम बन सकता है।

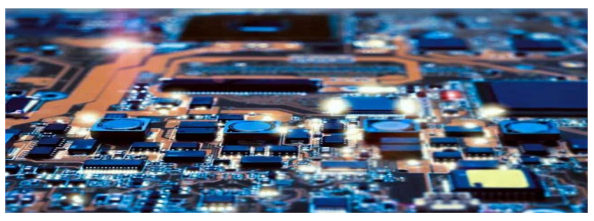

ऐप्पल को लगा बड़ा झटका, एक दिन में साफ हो गए कंपनी के 18, 276 अरब रुपए

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ऐप्पल को गुरुवार को बड़ा झटका लगा, जब उसके शेयरों में करीब 5इ की तेज गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से कंपनी की मार्केट वैल्यू में लगभग 202 अरब डॉलर (करीब 18, 276 अरब रुपए) की कमी आ गई। साल 2026 में यह कंपनी के लिए अब तक का सबसे खराब कारोबारी दिन माना जा रहा है, जिससे पूरे टेक सेक्टर में हलचल तेज हो गई है।

मार्केट डेटा के अनुसार, इस गिरावट के बाद पिछले एक साल में शेयरों में हुई अधिकांश बढ़त लगभग खत्म हो गई है। अप्रैल 2025 के बाद यह सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है और कंपनी के इतिहास में एक दिन की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू लॉस के रूप में देखी जा रही है। इससे पहले 3 अप्रैल 2025 को टैरिफ से जुड़ी घोषणाओं के बाद कंपनी को 311 अरब डॉलर का झटका लगा था।

गिरावट की प्रमुख वजह कंपनी के वॉयस असिस्टेंट अपडेट में देरी की खबरें बनीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच नए फीचर्स को लेकर निवेशकों की उम्मीदें काफी ऊंची थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी गूगल के एडवांस एआई मॉडल से जुड़े फीचर्स पर काम कर रही है लेकिन अपडेट चरणबद्ध तरीके से जारी हो सकता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसकी योजनाएं तय समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। हालांकि दबाव के बावजूद कंपनी का बिजनेस प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। हालिया तिमाही नतीजों में अच्छा मुनाफा दर्ज किया गया और कंपनी ने स्मार्टफोन बाजार में सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए टॉप सेलिंग ब्रांड का दर्जा भी हासिल किया है।

रूस पर घटेगी निर्भरता? वेनेजुएला से कच्चे तेल खरीदने के लिए रिलायंस को अमेरिका से मिली हरी झंडी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को वेनेजुएला के कच्चे तेल की सीधी खरीद के लिए अमेरिका से लाइसेंस मिल गया है। इस अनुमति से देश की सबसे बड़ी निजी रिफाइनिंग कंपनी आरआईएल रियायती दर पर उपलब्ध भारी कच्चे तेल का आयात कर सकेगी। वेनेजुएला का कच्चा तेल गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस रिफाइनरी की संरचना के अनुकूल है और उसके रिफाइनिंग मार्जिन को बेहतर बना सकता है।

इस मामले से परिचित सूत्रों ने कहा कि जनवरी के अंत में अमेरिका ने कुछ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को वेनेजुएला से सीधे तेल खरीदने की सामान्य अनुमति दी। इससे पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला से सीधे तेल खरीद पर रोक लगी हुई थी और तेल की आपूर्ति कारोबारियों के माध्यम से हो रही थी। पिछले महीने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाकर अमेरिकी जेल में भेज दिए जाने के बाद से ही वेनेजुएला के कच्चे तेल की सीधी खरीद शुरू होने

की उम्मीद जताई जा रही थी।

उसके बाद से अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों को शिथिल भी कर दिया है। हालांकि वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने का अमेरिकी लाइसेंस मिलने के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई। गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग परिसर संचालित करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पहले वेनेजुएला के कच्चे तेल की नियमित खरीदार थी। हालांकि 2019-20 में वेनेजुएला की मादुरो सरकार पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह आयात रुक गया था। लेकिन वर्ष 2024 में मिली अस्थायी राहत के दौरान रिलायंस ने वेनेजुएला से तेल खरीदा था। इस साल कारोबारियों के जरिये तेल खरीद दोबारा शुरू होने पर रिलायंस ने विटॉल कंपनी से 20 लाख बैरल तेल खरीदा है।

इस छूट का फायदा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी उठाया है। इन दोनों सरकारी तेल कंपनियों ने कुल मिलाकर 20 लाख बैरल कच्चा तेल वेनेजुएला से खरीदा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस से तेल खरीद रोकने और अमेरिका सहित अन्य स्रोतों से तेल आयात बढ़ाने पर सहमति जताई है। सूत्रों ने कहा कि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना कच्चे तेल की खरीद के स्रोतों में विविधता लाने की भारतीय रणनीति का हिस्सा है। रूस से तेल का आयात घटने की संभावना के बीच वेनेजुएला का तेल महत्वपूर्ण हो जाता है। वेनेजुएला का ओरिनोको बेल्ट क्षेत्र अपने भारी और बहुत-भारी ग्रेड के कच्चे तेल के लिए जाना जाता है।

शेयर बाजार में मचा कोहराम, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम, 4 बड़े कारणों ने किया निराश

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार (13 फरवरी) को बड़ी गिरावट देखने को मिली। बाजार खुलते ही दबाव में आ गया और दिनभर बिकवाली हावी रही। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 25, 550 के अहम स्तर से नीचे फिसल गया। आईटी शेयरों में भारी बिकवाली और कमजोर वैश्विक संकेतों ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया, जिससे लगभग सभी सेक्टर लाल निशान में रहे। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी करीब 1.5 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई।

कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1048.16 अंकों की गिरावट के साथ 82, 626.76 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 336.10 अंक टूटकर 25, 471.10 के स्तर पर आ गया।

बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह आईटी कंपनियों के शेयरों में लगातार बिकवाली रही। पिछले कुछ सत्रों से आईटी सेक्टर दबाव में है और कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बदलावों को लेकर निवेशकों की चिंता बढ़ी है, क्योंकि इससे पारंपरिक आईटी बिजनेस मॉडल और मार्जिन पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

एशियाई और अमेरिकी बाजारों में कमजोरी ने भी घरेलू बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ा। टेक और सॉफ्टवेयर शेयरों में वैश्विक स्तर पर गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया।

धनुष संग वेलेंटाइन डे पर सात फेरे लेने की खबर पर मृणाल ठाकुर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मेरी हल्दी सम्पन्न और आज

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के प्रमोशन में जोर-शोर से जुड़ी हुई हैं। मृणाल फिल्म के बीच पिछले काफी समय से साउथ सुपरस्टार धनुष संग डेटिंग और शादी की अफवाहों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब लोगों ने दोनों की शादी की तारीख भी तय कर दी। हालांकि, अब मृणाल ने धनुष के साथ डेटिंग और शादी की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने 14 फरवरी वेलेंटाइन डे पर धनुष के साथ शादी करने की अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा कहा है, जिसे सुनकर फैंस भी शॉक्ड रह जाएंगे।

हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू मे मृणाल ठाकुर ने धनुष संग अपनी शादी की अफवाहों पर खुलकर बात की और शादी पर अपने नजरिए को लेकर कहा कि, सिर्फ शादी करने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। एक्ट्रेस ने कहा, 'जब सही समय आए, जब आपको सही इंसान मिल जाए जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों और जिसकी खामोशी भी आपको परेशान न करें। तब आपको शादी का फैसला लेना चाहिए।' वहीं जब इंटरव्यू के दौरान मृणाल को बताया कि, सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक, शनिवार को उनकी शादी होने वाली है, तो वह हंस पड़ीं और ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर फैंस भी शॉक्ड रह जाएंगे। एक्ट्रेस ने मजाकिया लहजे में कहा, 'गाइज, आज मेरी हल्दी है और कल संगीत।वहीं इस दौरान मृणाल के साथ मौजूद उनकी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' के को-स्टार सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी मजे लेते हुए कहा कि, 14 फरवरी को सबको मृणाल के घर के बाहर लाइन लगा लेनी चाहिए।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सामान्य अस्पताल, सायन, मुंबई - 400 022
क्रमांकः एल.टी.एच./12/टी दिनांकः 13/02/2026

ई-निविदा सूचना

यह एक ई-निविदा सूचना है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त द्वारा नीचे विवरणानुसार त्रि-पैकेट प्रणाली के अंतर्गत ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा की प्रति 'ई-प्रोक्योरमेंट' अनुभाग के अंतर्गत महाटेंडर्स पोर्टल (https://mahatenders.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है।

विषयः एल.टी.एम.जी. अस्पताल के अस्थि रोग विभाग हेतु बैटरी संचालित पावर टूल आरी (4 नग) की आपूर्ति, आठ वर्ष की वारंटी सहित।

बिड क्रमांकः 2026_एमसीजीएम_1272153_1

ई-निविदा शुल्क (रुपये में)	बयाना राशि / ईएमडी (रुपये में)	ऑनलाइन निविदा डाउनलोड प्रारंभ तिथि एवं समय	ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय
3,630 रुपये/- + वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) @ 18 प्रतिशत	40,000 रुपये/-	12.02.2026 सायं 04:00 बजे (16:00 घंटे)	20.02.2026 सायं 04:00 बजे (16:00 घंटे)

इच्छुक निविदादाता निविदा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए महाटेंडर्स पोर्टल की वेबसाइट http://www.mahatenders.gov.in पर अवश्य जाएँ।

निविदा दस्तावेज डाक द्वारा न तो जारी किए जाएंगे और न ही स्वीकार किए जाएंगे।

डीन
पीआरओ/2982/विज्ञा./2025-26 एल.टी.एम.जी. अस्पताल, सायन।

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

मंत्री विजय शाह के समर्थन में उतरा आदिवासी और ओबीसी समाज

कहा-8 बार के मंत्री 4 बार मांग चुके माफी, केस खारिज हो

भोपाल **(एजेंसी)**। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान को लेकर मंत्री विजय शाह की मुश्किलें वैसे को आए दिन के साथ बढ़ती जा रही है लेकिन अब उनके पक्ष में समाज लामबंद होता दिखाई दे रहा है। अब मंत्री विजय शाह के समर्थन में आदिवासी समाज के साथ ही छात्र संगठन खुलकर सामने आ गए हैं और मंत्री का पक्ष ले लिया है।समाज का कहना है कि अपनी गलती के लिए विजय शाह चार बार सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं, इसलिए अब इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए और मामले को खत्म कर देना चाहिए।

जनजातीय कार्यमंत्री कुंवर विजय शाह के बयान से उपजे विवाद को लेकर अब आदिवासी समाज और छात्र संगठन ने उनके पक्ष में मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को विजय शाह मित्र मंडल और अजा-जजा के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। समाज के युवाओं का कहना है कि मंत्री शाह भाषाई त्रुटि के लिए चार बार सार्वजनिक तौर से माफी मांग चुके हैं, इसलिए उनकी जनता के प्रति सेवा और वरिष्ठता को देखते हुए ये मामला समाप्त कर देना चाहिए।

आदिवासी समाज, छात्र संगठन और ओबीसी वर्ग के प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि विजय शाह आदिवासी समाज के सर्वमान्य नेता हैं, लगातार आठ बार से विधायक चुने गए हैं, यह उनकी लोकप्रियता और जनसेवा का प्रमाण है। रविंद्र आदिवासी, बुद्धि आदिवासी, उदयभान आदिवासी, नरेंद्र बंजारा का कहना है कि शाह की शुरू की गई योजनाएं आज भी जनता के लिए हितकारी हैं। इसलिए अनजाने में हुई एक भाषाई त्रुटि के कारण गलत ठहराकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मंत्री शाह ने गलती के लिए एक बार नहीं बल्कि 4 बार माफी मांगी है। अगर कोई चार बार सार्वजनिक मंचों से माफी मांगता है तो फिर मामले को तूल नहीं देना चाहिए । इसलिए आदिवासी समाज की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रपति से इस विवाद को समाप्त करने और मागी को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

कुंभ कल्प में त्रिकालदर्शी का दिव्य दरबार, श्रद्धालु हुए भावविभोर

राजिम। पवित्र तीर्थ नगरी राजिम में आयोजित कुंभ कल्प के पावन अवसर पर त्रिकालदर्शी श्री पंडोखर सरकार जी का दिव्य दरबार निरंतर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है।

दरबार के दूसरे दिन शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा मेला परिसर भक्ति व उत्साह से गूंज उठा। आज प्रातः पंडोखर सरकार जी की भव्य शोभायात्रा बैंड-बाजे, रथ एवं बाजे-गाजे के साथ निकाली गई। शोभायात्रा में शिष्य मंडल के सदस्य राजीव अवस्थी, राकेश अग्रवाल, जितेंद्र सोनी, बिंदु शर्मा, उमा शंकर शास्त्री, टेकराम साहू, विनोद तिवारी, विकास दुबे, अजय सोनी सहित अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। शोभायात्रा के पश्चात मेला परिसर मे दिव्य दरबार का विधिवत शुभारंभ हुआ।

दरबार में उपस्थित श्रद्धालु उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब यह बताया गया कि गुरुदेव ने 13 फरवरी को आने वाले श्रद्धालुओं के विषय में पर्चियां एक दिन पूर्व 12 फरवरी की रात्रि में ही लिख दी थीं। बिना देखे और बिना पूछे लोगों के जीवन से जुड़ी बातें बताने की घटनाओं ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया।

दरबार में एक युवती की समस्या का उल्लेख करते हुए गुरुदेव ने कथित रूप से उसे ब्लैकमेल करने वाले युवक का नाम बताया और युवती को शीघ्र विवाह का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि अन्याय करने वाले को ईश्वर स्वयं दंड देंगे। इसके अतिरिक्त संतान प्राप्ति की कामना लेकर आए अनेक दंपतियों को भी आशीर्वाद प्रदान किया गया।

आयोजकों के अनुसार, 14 फरवरी 2026 को दरबार का अंतिम दिन रहेगा। अंतिम दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए विशेष 'गोद भराई' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

राजिम कुंभ कल्प में चल रहा यह दिव्य दरबार श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बना हुआ है।

पिता ने अपनी विधवा बेटी का किया पुनर्विवाह, समाज ने किया बहिष्कार, 10 साल तक गांव में नो एंट्री

बालाघाट **(एजेंसी)**। आजादी के 78 वर्ष बाद भी समाज से कुरीतियां पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई हैं। बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र स्थित मंडई टेकरी में एक पिता को अपनी विधवा बेटी की दोबारा शादी कराना भारी पड़ गया। समाज ने पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ 10 वर्ष का सामाजिक प्रतिबंध भी लगा दिया। पीड़ित पिता मानिक सोनवाने ने मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की है। कलेक्टर मृणाल मीना ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। मानिक सोनवाने ने बताया कि उनकी बेटी की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन वर्ष 2022 में बीमारी के कारण दामाद का निधन हो गया। उस समय बेटी की उम्र मात्र 22 वर्ष थी। बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उन्होंने उसका पुनर्विवाह कराया, जिसके

बाद बिझवार समाज के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ने बैठक कर परिवार के बहिष्कार का निर्णय सुना दिया।

इस फैसले के तहत परिवार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और 10 साल का सामाजिक बहिष्कार लागू किया गया। इसी तरह का एक अन्य मामला 3 फरवरी को लालबर्रा के देवरी गांव में सामने आया था, जहां फोगल बाहेश्वर ने अपने भांजे का अंतरजातीय विवाह कराया था। इसके बाद मरार समाज ने उसे भी बहिष्कृत कर दिया। इस मामले की जांच भी जारी है। 21वीं सदी में जब देश डिजिटल इंडिया और अंतरिक्ष मिशनों की बात कर रहा है, ऐसे में सामाजिक बहिष्कार और जुर्माने जैसे फैसले संविधान और कानून की भावना पर सवाल खड़े करते हैं। प्रशासन ने दोनों मामलों में जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

जिम से बाहर निकलते ही कारोबारी की गोलियां मारकर हत्या, चारों तरफ मची अफरा-तफरी

देहरादून **(एजेंसी)**। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपराध की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। महज 48 घंटे के भीतर दूसरी और 11 दिनों में तीसरी हत्या ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात करीब 1:15 बजे राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब जिम से बाहर निकल रहे 50 वर्षीय कारोबारी विक्रम शर्मा को अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। वारदात की जगह एसएसपी आवास से लगभग 500 मीटर दूर बताई जा रही है, जिससे पुलिस की चौकसी पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधीक्षक (नगर) प्रमोद कुमार ने बताया कि मृतक का उधमसिंह नगर में स्टोन क्रशर से जुड़ा कारोबार था। घटना के बाद शहरभर में नाकेबंदी कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश तेज कर दी गई है।

लगातार हो रही वारदातों से देहरादून में भय का माहौल है। बुधवार

को तिब्बती मार्केट के बाहर गैस एजेंसी संचालक की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 2 फरवरी को मच्छी बाजार क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अब राजपुर रोड पर हुई इस गोलीकांड ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।

बाहरी तौर पर रियल एस्टेट कारोबारी की पहचान रखने वाले विक्रम शर्मा का अतीत विवादों से घिरा रहा है। उसके पिता टाटा स्टील में कार्यरत थे। परिवार बाद में देहरादून आ बसा, जबकि विक्रम ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जमशेदपुर में बिताया। सूत्रों के अनुसार, उसके खिलाफ झारखंड में 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 2017 में उसे देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और 2021 तक वह जेल में रहा। बाद में झारखंड हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद वह रिहा हुआ। पुलिस सूत्र बताते हैं कि विक्रम शर्मा का नाम झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह से भी जुड़ता रहा है, जिसे उसका करीबी माना जाता था। उस पर कई चर्चित मामलों में आरोप लगे थे, जिनमें टाटा स्टील के सुरक्षा अधिकारी की हत्या, व्यवसायियों पर फायरिंग और अन्य संगीन वारदातें शामिल थीं। हालांकि कई मामलों में वह बरी भी हो चुका था।

जेल से बाहर आने के बाद विक्रम शर्मा ने खुद को एक शांत और व्यवस्थित कारोबारी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। देहरादून में उसका दायरा रियल एस्टेट और व्यापारिक संपर्कों तक सीमित नजर आ रहा था। लेकिन ताजा वारदात ने यह साफ कर दिया कि उसका पुराना इतिहास अब भी उसके साथ जुड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और शहरवासी जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भाग लेने को लेकर उतावला हुआ पाकिस्तान, मगर मोदी ने चली सधी हुई चाल

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर बनने जा रहे बोर्ड ऑफ पीस को लेकर नई कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अगले सप्ताह वाशिंगटन में होने वाली इस मंच की पहली बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विदेश मंत्री इशाक दर भी उनके साथ रहेंगे। दूसरी ओर भारत ने वही निमंत्रण मिलने की बात स्वीकार करते हुए साफ किया है कि वह अभी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और सोच समझकर ही कोई कदम उठाएगा।

हम आपको बता दें कि यह मंच शुरुआत में गाजा के अस्थायी शासन और पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए सोचा गया था, पर बाद में ट्रंप ने इसे वैश्विक संघर्षों से निपटने वाला व्यापक मंच बताना शुरू कर दिया। यही बदलाव कई देशों और विशेषज्ञों की चिंता का कारण है। उन्हें डर है कि ऐसा कोई ढांचा संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमजोर कर सकता है। अभी तक कोई भी प्रमुख जी-7 देश औपचारिक रूप से इससे नहीं जुड़ा है, लेकिन पाकिस्तान उन शुरुआती देशों में रहा जिसने जल्दबाजी में हामी भर दी। पाकिस्तान का दावा है कि वह यह कदम भले मन से उठा रहा है और वह आठ इस्लामी अरब देशों की सामूहिक आवाज का हिस्सा है। वह फिलिस्तीन के लिए 1967 से पहले की सीमा के आधार पर अलग राज्य और अल कुद्स को राजधानी बनाने की बात दोहरा रहा है। सुनने में यह नैतिक रुख लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मंच से सच में ऐसा कोई समाधान निकलेगा या यह केवल बड़ी शक्तियों की छवि चमकाने का जरिया बनेगा।

इधर नई दिल्ली का रुख कहीं अधिक परिपक्व और संतुलित दिखता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद के हर प्रयास का समर्थन करता है, पर किसी भी पहल में शामिल होने से पहले उसके ढांचे, लक्ष्य और प्रभाव का ठंडे दिमाग से आकलन जरूरी है। यही जिम्मेदार शक्ति की पहचान है। हर मंच पर पहुंच जाना कूटनीति नहीं, कई बार संयम ही असली कूटनीति होता है।

पाकिस्तान की आतुरता का एक कारण उसकी वैश्विक छवि भी है। वह लंबे समय से खुद को शांति समर्थक देश दिखाने की कोशिश करता रहा है, जबकि जमीन पर उसका इतिहास उलटा रहा है। ऐसे में उसे हर वह मंच लुभाता है जहां वह अपने लिए जगह और तस्वीर दोनों हासिल कर सके। दावोस में फोटो अवसर मिल चुका है, अब वाशिंगटन में उपस्थिति से वह अपने लिए नई वैधता गढ़ना चाहता है। यह अलग बात है कि विश्व की बड़ी ताकतें अभी दूरी बनाए हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की एक और परत भी है। ट्रंप बार बार यह दावा दोहराते रहे हैं कि पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव को उन्होंने रुकवाया। भारत इस दावे को साफ नकार चुका है और कह चुका है कि अपने सुरक्षा हितों पर वह किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। ऐसे में बोर्ड ऑफ पीस जैसा मंच कहीं न कहीं कथानक की लड़ाई का भी मैदान बन सकता है। कौन शांति दूत दिखेगा और किसकी कहानी चलेगी, यह भी दांव पर है। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को देखते हुए पाकिस्तान को डर है कि कहीं नई दिल्ली और वाशिंगटन के सुधरते रिश्ते उसके लिए मुश्किल न बन जाएं, इसलिए भी शहबाज शरीफ भागे भागे अमेरिका जा रहे हैं।

देखा जाये तो भारत का सतर्क रुख सराहना के योग्य है। विश्व राजनीति में हर चमकती पहल सोना नहीं होती। किसी भी नए मंच में शामिल होना केवल सद्भाव का मामला नहीं, बल्कि संप्रभुता, रणनीतिक स्वतंत्रता और दीर्घकालिक हितों से जुड़ा फैसला होता है। यदि कोई ढांचा संयुक्त राष्ट्र जैसी स्वीकृत संस्था को किनारे कर समानांतर व्यवस्था खड़ी करता है, तो उसके दूरगामी असर होंगे। भारत का ठहरकर देखना बताता है कि वह भावनाओं से नहीं, हितों से संचालित शक्ति है।

पाकिस्तान के लिए यह मंच मानो बेचैनी का इलाज है। उसे हर उस दरवाजे पर दस्तक देनी है जहां से उसे मान्यता, मदद या महत्व मिल सके। लेकिन केवल मंचों पर मौजूदगी से विश्वसनीयता नहीं बनती; वह नीतियों और आचरण से बनती है।

एमपी मर्डर मिस्ट्री : तीसरी पत्नी की हत्या कर सूटकेश में भरी लाश, गटर में डाला पति ने पूरे परिवार के साथ मिलकर की हत्या

भोपाल **(एजेंसी)**। राजधानी के निशातपुरा थाना क्षेत्र स्थित कमला नगर में सूटकेस में मिली महिला की लाश के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मृतका की पहचान महाराष्ट्र के गोंदिया निवासी सिया के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसकी हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके साथ रह रहे समीर और उसके परिवार ने मिलकर की थी।

पुलिस के अनुसार, समीर पिछले पांच महीनों से सिया के साथ रह रहा था। दोनों की मुलाकात अक्टूबर में हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके बीच अक्सर विवाद होता था। शुरुआती महीनों में सिया, समीर की पत्नी के साथ ही रह रही थी, लेकिन बढ़ते विवाद के चलते पत्नी जबलपुर चली गई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि सिया की गला घोंटकर हत्या की गई। हत्या के बाद समीर ने अपने भाई चांद की मदद से शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। शव को सूटकेस में रखा गया, उसमें पत्थर बांधे गए और रस्सी से कसकर बांधकर पानी की टंकी में डुबो दिया गया, ताकि वह ऊपर न आए। घटना का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय युवक चबूतरा पोतने पहुंचे और पानी में एक संदिग्ध बक्सा तैरता दिखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसी रस्सी की मदद से बक्से को बाहर निकाला, जिसमें महिला का शव मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद समीर जबलपुर अपनी दूसरी पत्नी को लेने चला गया था। जैसे ही वह भोपाल लौटा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुबह 5:30 बजे पुलिस ने समीर, उसकी पत्नी, भाई, बहन और मां को हिरासत में ले लिया।

पुलिस का कहना है कि पूरे परिवार ने मिलकर इस वारदात की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। समीर ने सिया से शादी नहीं की थी, लेकिन वह उसके साथ रह रहा था। बताया जा रहा है कि वह दोनों पत्नियों और सिया के साथ रिश्तों को लेकर तनाव में था।

तारिक रहमान की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने मिलाया फोन, बोले- मिलकर मजबूत करेंगे संबंध

ढाका **(एजेंसी)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, 13 फरवरी को फोन पर बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान को बधाई दी। उन्होंने एक पोस्ट में दोनों देशों के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर अपने बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। बीएनपी ने 13वें संसदीय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। नवीनतम रुझानों के अनुसार, बीएनपी ने 213 सीटें जीती हैं, जबकि जमात और उसके सहयोगियों ने 71 सीटें हासिल की हैं। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने एक सीट जीती है, अन्य दलों ने 6 सीटें जीती हैं। चुनाव में मुख्य रूप से बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच मुकाबला देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने चुनाव में भाग नहीं लिया, क्योंकि पार्टी भंग हो चुकी है।

बांग्लादेश में हुए चुनावों में 299 निर्वाचन क्षेत्रों में 127 मिलियन योग्य मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से लगभग आधे 18-37 वर्ष की आयु वर्ग के थे और 457 मिलियन पहली बार मतदान कर रहे थे। 50 से 59 पार्टियों के लगभग 1755 से 1981 उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनमें से बीएनपी ने 291 सीटें उतारीं और वह सबसे आगे रही; प्रतिबंधित अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया था।

भागते चीनी जहाज को जापान ने दबोचा, भारी एक्शन हो गया!

टोक्यो **(एजेंसी)**। जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अब जापान भी चीन के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में है। तभी तो साल 2022 के बाद अब जापान ने कुछ ऐसा किया है जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। जापानी अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम जापान के नागासाकी के पास अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक चीनी मछली पकड़ने वाले नाव को जब्त कर लिया। उसके कप्तान को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि नाव ने जापानी निरीक्षण टीम के आदेशों की अनदेखी कर भागने की कोशिश की। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान और चीन के बीच पहले से ही एक बड़ा कूटनीतिक विवाद चल रहा है।

जापान की फिशरी एजेंसी ने इस बयान को जारी करते हुए बताया कि 12 फरवरी की दोपहर के आसपास नागासाकी प्रीफेक्चर के गोतो द्वीप समूह के पास मेशिमा द्वीप से लगभग 89.4 नॉटिकल मील यानी कि करीब 165 कि.मी. दक्षिण पश्चिम में स्थित जापान की ईजेड में चीनी नाव क्यू ओंग डोंग यू 111998 को देखा गया। यह एक ट्रोलर प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव थी जिसमें जाले लगे हुए थे। फिश एजेंसी के पेट्रोल जहाज होकआ मारो ने नाव को रोकने और बोट पर निरीक्षण की

अनुमति देने का आदेश दिया। लेकिन कप्तान ने आदेश की अवहेलना की और नाव भगाने लगा। इसके बाद जापानी अधिकारियों ने नाव को जब्त कर लिया और उसके 47 वर्षीय चीनी कप्तान को भी गिरफ्तार किया गया। नाव पर कुल 11 चालक दल के सदस्य थे जिनमें से कप्तान को हिरासत में लिया गया। बाकी सदस्यों की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)